दमण से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

Asli Azadi Dainik @AsliAzadiDainik

asliazadidainikofficial

# असली आज़ादी

■ वर्षः 21, अंकः 307 ■ दमण, गुरुवार 27, अगस्त 2026 ■ पृष्ठः 8 ■ मूल्यः 2 रु ■ RNI NO-DDHIN/2005/16215 ■ संपादक- विजय जगदीशचंद्र भट्ट

## भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां केवल देश के वैध नागरिकों को ही रहने का अधिकार: गृह मंत्री अमित शाह

■ अवैध घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा, जनसांख्यिकी के लिए खतरा: गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली,(ईएमएस)। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहां केवल देश के वैध नागरिकों को ही रहने का अधिकार है। इस सम्मेलन में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की मौजूदगी में उन्होंने अवैध घुसपैठ पर प्रहार किया। शाह ने सुरक्षा तंत्र को आगाह करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के लिए गंभीर खतरा हैं।

उन्होंने साफ किया कि देश के संसाधनों और सुरक्षा पर पहला हक केवल भारत के नागरिकों का है। सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को सख्त रुख अपनाना होगा। शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है; यहां रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को है। इस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के प्रमुख शामिल हुए थे। घुसपैठियों से देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और डेमोग्राफी को खतरा बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पिछले आठ महीनों में, जमीनी सीमा साझा करने वाले सभी राज्यों का दौरा करने के बाद, हमने राज्यों के साथ सीमा सुरक्षा के लिए चार-सूत्रीय रणनीति वाला एक दस्तावेज साझा किया है। हमारा लक्ष्य बहुत कम समय में देश को घुसपैठियों से मुक्त बनाना है। शाह ने कहा कि भारत की सुरक्षा नीति वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा और संसाधनों को लेकर असुरक्षा, सप्लाई-चेन में रुकावट, बढ़ते कट्टरपंथ और साइबर गलत सूचनाओं के जरिए होने वाले युद्ध को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मजबूत आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित भारत के लिए जरूरी है। अगर भारत को हर क्षेत्र में सबसे आगे आना है, तो उसकी आंतरिक सुरक्षा को और मज़बूत करना होगा। दो दिन की एनसीसी कॉन्फ्रेंस के दौरान, इंटेलिजेंस एजेंसियों और सुरक्षा बलों ने घुसपैठ, आतंकी समूहों के खिलाफ रियल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने और उनके लॉजिस्टिक्स और फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की। अमित शाह ने 27 मार्च को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 पर बहस का जवाब देते हुए भी ऐसी ही बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि जो लोग भारत की समृद्धि में योगदान देने के लिए कानूनी तौर पर आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अवैध रूप से आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जब 19 मई को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने गैर-कानूनी गतिविधि के तहत सात साल की सजा काटने के बाद डिपोर्टेशन का सामना कर रहे एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक की हिरासत में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि क्या भारत को दुनिया भर से आने वाले शरणार्थियों को पनाह देनी चाहिए? हम पहले ही 140 करोड़ की आबादी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि हम कहीं से भी आने वाले विदेशी नागरिकों की मेहमाननवाजी करते रहें। अधिकारियों से अगले 15 से 20 सालों के रुझानों पर गौर करने को कहते हुए शाह ने कहा कि उन्हें उन समस्याओं की पहचान करनी चाहिए जो पैदा हो सकती हैं और उनसे निपटने की रणनीतियां बनानी चाहिए। उन्होंने राज्य पुलिस बलों को 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 को जमीनी स्तर पर लागू करने और ड्रग-मुक्त भारत बनाने के लिए तीन डिटेक्ट (पता लगाना), डिसरप्ट (बाधा डालना) और डिस्ट्रॉय (नष्ट करना)' पर काम करने का निर्देश भी दिया।

## ओबीसी क्रीमी लेयर: केंद्र की अपील से आईएएस-आईपीएस कैडर में बदलाव का डर

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर के नियम तय करने के लिए दो साल का समय मांगा है। केंद्र सरकार ने साथ ही 11 मार्च के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पिछली तारीख से लागू करने के खिलाफ अपनी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। इस फैसले में सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) या निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता के वेतन के आधार पर ओबीसी उम्मीदवारों के क्रीमी लेयर वर्गीकरण को खारिज किया गया था। केंद्र सरकार का तर्क है कि बीती पिछली तारीख से लागू करने पर सिविल सेवाओं, खासकर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मच सकती है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच से रोहित नाथन मामले में 11 मार्च के फैसले पर कुछ स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। मेहता ने कहा कि यदि इस फैसले को पिछली तारीख से लागू किया जाता है, तब क्रीमी लेयर वाले ओबीसी उम्मीदवारों के पुराने बैच का स्टेटस बदलकर नॉन-क्रीमी करना होगा। इससे सिविल सर्विस में उनके कैडर, पद और सर्विस में बदलाव करना होगा, जिसका सीधा असर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) जैसे प्रमुख कैडर में लंबे समय से कार्यरत अधिकारियों पर पड़ेगा और इससे बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मच जाएगी। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने स्पष्ट किया कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा या उसमें बदलाव नहीं चाहता, बल्कि वह सिर्फ पिछली तारीख से लागू करने में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और उसके गंभीर नतीजों से कोर्ट को अवगत कराना चाहता है। मुख्य न्यायाधीश ने 1 सितंबर को केंद्र की अर्जियों को सूचीबद्ध करने पर सहमति जाहिर की है। अपनी अर्जी में केंद्र ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में आने वाली गंभीर चुनौतियों को देखकर केंद्र सरकार एक ऐसी नीति लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो कोर्ट की टिप्पणियों पर प्रभावी ढंग से अमल करे और निष्पक्ष हो। केंद्र सरकार ने कहा कि

### ■ अफरा-तफरी की आशंका

बिना किसी उचित नीति के इस फैसले को लागू करने से केंद्र और 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली सरकारी भर्तियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिलों पर दूरगामी और नकारात्मक असर पड़ेगा। रेलवे, बैंक, डाक विभाग और अर्धसैनिक बलों जैसे बड़े संगठनों को भी क्रीमी लेयर के पुराने वर्गीकरण को चुनौती देने वाली लाखों अर्जियों और कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि क्रीमी लेयर का मामला 1992 के इंदिरा साहनी फैसले के बाद सामने आया था, जिसके बाद 8 सितंबर 1993 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। इसमें ओबीसी के उन वर्गों की पहचान के नियम बताए गए थे, जिन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना था। 11 मार्च के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने का आधार 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया कि काम-धंधे की कैटेगरी होनी चाहिए, न कि केवल निजी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता की आय से होना चाहिए।

## संघ प्रदेश थ्रीडी की विकास यात्रा के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भीमपोर पंचायत घर पर प्रशासन आपके द्वार और हेल्थ कैंप का हुआ आयोजन

■ मरवड, कडैया, भीमपोर, दुनेठा, भेंसलोर एवं वरकुंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के नागरिकों ने लिया लाभ

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में प्रदेश में विकास यात्रा के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दस साल बेमिसाल थीम के तहत 26 अगस्त 2026 को दमण के भीमपोर पंचायत घर में प्रशासन आपके द्वार और हेल्थ कैंप लगाया गया। इस कैंप में मरवड, कडैया, भीमपोर, दुनेठा, भेंसलोर और वरकुंड ग्राम पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशासन आपके द्वार पहल का मकसद सरकारी सेवाओं को गांव के लोगों के करीब लाना, वेलफेयर स्कीमों तक पहुंच आसान बनाना, सरकारी प्रोग्रामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान पक्का करना था। कैंप के दौरान, दमण जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पावर/इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट, लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, फूड और सिविल सप्लाइज़ डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लीड बैंक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट और हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ, सरकारी सर्विस देने, अलग-अलग वेलफेयर स्कीम के तहत एनरोलमेंट में मदद करने और अलग-अलग सरकारी स्कीम और प्रोग्राम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मौजूद थे। हेल्थ कैंप में लोगों को पूरी हेल्थ स्क्रीनिंग, जागरूकता और जरूरी हेल्थकेयर सर्विस दी गईं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दमण ने ह्यूमन पेपिलोमावायरस, ट्यूबरकुलोसिस, कम्युनिकेबल और नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों और वेक्टर-बॉर्न बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई। टीबी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग की गई। साथ ही आँखों का चेक-अप और इम्यूनाइजेशन सर्विस भी दी गईं। हेल्थ कैंप के दौरान 80 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। कैंप में वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, सखी-वन स्टॉप सेंटर, नशा मुक्त भारत अभियान, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, सेल्फ-हेल्प ग्रुप, महिलाओं के प्रोडक्ट्स, सेल्प हेल्प ग्रुप की ट्रेनिंग की जरूरतों के लिए सुविधा, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ-साथ सरकार की दूसरी भलाई की पहलों के बारे में भी जानकारी दी गई। कैंप के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों ने आकर अलग-अलग सरकारी स्कीमों और प्रोग्राम के बारे में पूछताछ की। इस पहल से गांव के लोगों को सरकारी अधिकारियों से सीधे बातचीत करने और अपने घर पर अलग-अलग पब्लिक सर्विस और भलाई की स्कीमों का फायदा उठाने का मौका मिला। इस अवसर पर दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल, कडैया जिला पंचायत सदस्य हर्षल पटेल, भीमपोर ग्राम पंचायत सरपंच उदय पटेल, वरकुंड ग्राम पंचायत सरपंच डॉ. विजय पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रशासन आपके द्वार पहल के तहत 27 अगस्त 2026 को मगरवाडा ग्रुप ग्राम पंचायत में पटलारा, मगरवाड़ा, परियारी, दमणवाड़ा और कचीगाम ग्राम पंचायतों के लोगों के लिए एक कैंप लगाया जाएगा। मगरवाड़ा ग्राम पंचायत में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा।

## डीएमसी ने प्रशासक प्रफुल पटेल के संघ प्रदेश में शासन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किये सेवाकीय कार्य

■ डीएमसी प्रेसिडेंट दीपिका टंडेल, वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पटेल एवं काउंसिलरों ने गौ सेवा के साथ बच्चों को बांटे बिस्किट

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव प्रशासक प्रफुल पटेल के शासन को प्रदेश में 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दमण नगरपालिका की टीम द्वारा विभिन्न सेवा के कार्य किये गये। इस दौरान डीएमसी की टीम ने कचीगाम स्थित गौ शाला पहुंचकर गौ सेवा की। इस मौके पर डीएमसी प्रेसिडेंट दीपिका टंडेल, वाइस प्रेसिडेंट मुकेश पटेल ने गौ माता को हरा चारा और गुड खिलाकर सेवाकीय कार्य किया। इसके साथ ही छोटे बच्चों को बिस्किट भी बांटे गये। इस दौरान काउंसिलरों में अस्पी दमणिया पीयूष पटेल, कल्पेश सीताराम, कपिला ओड, नीला राणा की मौजूदगी रही।

## हिमाचल में भूकंप, किचन में रखे वर्तन गिरे, सुबह-सुबह लगे झटके लोग घरों से निकले

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल की राजधानी शिमला सहित आस पास के शहरों में आए भूकंप ने लोगों को डरा दिया। घरों की किचन में रखे वर्तन गिरने लगे। जब तक लोग समझ पाते तब तक झटके लगने लगे। लोग डर के चलते घरों से बाहर निकले तब पता चला कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। सुबह 5 बजकर 46 मिनट और 50 सेकंड पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई। इसका केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे जुब्बल-कोटखाई की तरफ था। यह झटका लगभग तीन सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके दौरान धरती डोलने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि, उस समय कई लोग नींद में थे, जिस वजह से उन्हें इसका पता नहीं चल पाया। कुछ नागरिकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तेज झटका लगने की जानकारी साझा की। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी के कई अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके अनुभव किए गए। गनीमत यह रही कि इस घटना में फिलहाल किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील राज्यों में आता है, जिसमें शिमला और मंडी जैसे जिले जोन-4 और जोन-5 के अंतर्गत आते हैं। सामान्य तौर पर 5.0 से कम तीव्रता वाले भूकंपों से बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना कम होती है। इससे पहले हाल ही में चंबा और कांगड़ा जिलों में भी भूकंप के झटके दर्ज किए जा चुके हैं। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

## गोवा कैबिनेट का ऐतिहासिक कदम : गैर-कानूनी धर्मांतरण पर उम्रकैद की सजा का प्रस्ताव

पणजी (एजेंसी)। गोवा कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्म परवर्तन निषेध विधेयक 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। यह विधेयक जबरन, दबाव, लालच, धोखाधड़ी या शादी के मकसद से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करता है। प्रस्तावित कानून के तहत इसतरह के मामलों में दोषियों को उम्रकैद तक की सजा, न्यूनतम 50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। विधेयक प्रावधान करता है कि यदि कोई शादी केवल गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से की गई हो, तब उस शादी को अमान्य घोषित किया जा सकता है। धर्मांतरण में शामिल दोषियों को कम से कम तीन साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल हो सकती है। यदि धर्मांतरण का शिकार कोई नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, तब यह सजा 5 से 14 साल की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ सकती है। मुख्य सचिव वी. कंडावेलू ने इस कानून के उद्देश्य पर कहा कि इसका मकसद कमजोर और भोले-भाले लोगों को अनुचित तरीकों से होने वाले धर्मांतरण से बचाना है। प्रस्तावित कानून के अनुसार, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा, जबकि धर्मांतरण समारोह आयोजित करने वाले व्यक्ति को रस्म से एक महीने पहले जानकारी देनी होगी।

## कंगना के पलटवार से सन्न बाबा रामदेव : जवानी पर सवाल उठाना पड़ा भारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योगगुरु बाबा रामदेव के बीच छिड़ा जुबानी जंग अब व्यक्तिगत हमलों में बदल गया है। कंगना के विवादित जनरेशन गटर बयान से शुरू हुआ यह मामला, रामदेव द्वारा उनकी जवानी और अतीत पर सवाल उठाने के बाद तीखे व्यक्तिगत पलटवार में बदल गया। कंगना के करारे जवाब से सन्न हुए रामदेव को आखिरकार यह कहना पड़ा कि वह विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल, जंतर-मंतर पर युवाओं को जनरेशन गटर कहने पर उठे विवाद के बीच, जब बाबा से कंगना के बयान पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने अभिनेत्री-सांसद पर हमला बोल दिया। रामदेव ने कहा था, 'उनका बचपन कैसा था? उनकी जवानी कैसी थी? उनके पिछले काम कैसे थे? मैं इसतरह के लोगों पर बात नहीं करना चाहता। युवाओं को जनरेशन गटर कहना विकृत मानसिकता की निशानी है।' रामदेव के इन्हीं निजी टिप्पणियों पर सांसद कंगना ने तत्काल और तीखा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिवास्वप्न मत देखिए। अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही कुछ भी मान सकते हैं। कम से कम मुझे झूठे या भ्रामक प्रभावकारिता दावों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी।' कंगना यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने रामदेव को चरित्र पर उपदेश देने से साफ मना किया और दो टूक कहा, 'मुझे कैरेक्टर लेसन मत दीजिए। तुमसे तब बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर। नो फ्रॉड डिटेक्टेड हियर।' यह पलटवार पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की ओर इशारा था, जहां 2024 में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी थी।

# प्रलयकारी बाढ़ से नेपाल में तबाही, 90 की मौत और 150 भारतीयों सहित 700 लोग लापता

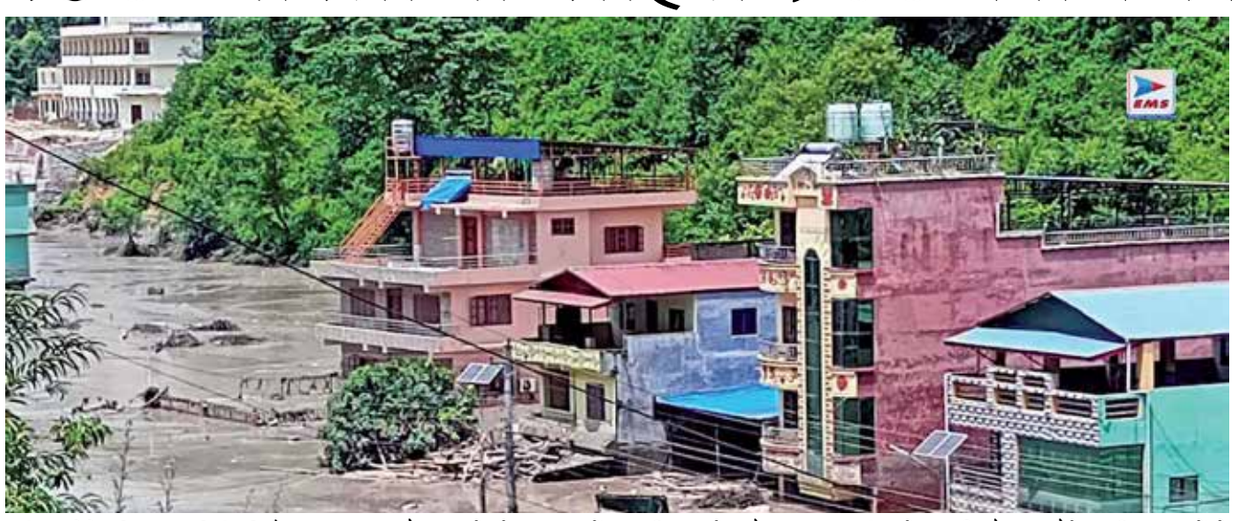

काठमांडू (ईएमएस)। नेपाल में 26 अगस्त को भोटे कोशी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हिमालय की संकरी घाटियां भी उसकी प्रचंड धारा के सामने बेबस नजर आईं। तिब्बत से निकलकर नेपाल पहुंचने वाली इस नदी में अचानक बढ़े जलप्रवाह ने सिंधुपाल्चोक जिले में भारी तबाही मचा दी। नदी का वेग इतना तेज था कि कई स्थानों पर पुल टूट गए, सड़कें और रास्ते बह गए तथा नदी किनारे बसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ। उफनती धारा अपने साथ चट्टानें, पेड़ और मलबा बहाती हुई आगे बढ़ती रही। स्थानीय इलाकों से सामने आए दृश्यों में नदी का पानी काला-भूरा और मटमैला दिखाई दे रहा है तथा ऊंची-ऊंची लहरें संकरी घाटियों से होकर बेहद तेजी से गुजर रही हैं।

अब तक करीब 90 लोगों की मौत की खबर है, जबकि लगभग 700 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन लापता लोगों में लगभग 150 भारतीय पर्यटक शामिल होने की जानकारी मिली है। राहत और बचाव अभियान के बीच तबाही का वास्तविक आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

स्थिति की गंभीरता को देखकर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है, जिसमें 15 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। बाढ़ के तेज बहाव में कई वाहन और अन्य सामान बह गए हैं। कुल 13 जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनके बांध, विद्युतगृह, पहुंच मार्ग और अन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची है। काठमांडू ट्रैफिक पुलिस ने एहतियात के तौर पर काठमांडू से रसुवा, नुवाकोट, चितवन और धादिङ जाने वाले वाहनों की आवाजाही को रोक दिया है।

बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। नेपाल सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल राजाराम बस्नेत ने बताया कि बुसी और तुसु जैसे प्रभावित इलाकों से 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। कुल 15 हेलीकॉप्टरों में से 7 नेपाली सेना के और 8 अन्य एजेंसियों के हैं, जो बचाव अभियान में लगे हैं। घायलों के उपचार के लिए मछली ट्रेनिंग कैंप में एक मेडिकल सेंटर स्थापित किया गया है, और प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल व बचाव टीमें तैनात की गई हैं। स्थानीय अधिकारियों और नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के खतरे को लेकर पहले ही अलर्ट कर दिया गया था।

अधिकारियों का कहना है कि सेना और मेडिकल टीमें फिलहाल बचाव कार्य पर केंद्रित हैं, और मृतकों व घायलों की सटीक संख्या का आकलन अभी जारी है। व्यापक नुकसान का विस्तृत आकलन स्थलीय निरीक्षण के बाद ही किया जा सकेगा। इस बीच, नेपाल में आई इस बाढ़ के मद्देनजर बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है।

गंडक नदी में संभावित फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

## लोकसभा स्पीकर ने टीएमसी से 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दायर की थी। इस मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। यह घटनाक्रम तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर उन 20 सांसदों से जवाब मांगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सांसदों को नोटिस जारी किया और स्पीकर के पास लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द विचार करने को कहा है। लोकसभा स्पीकर और सेक्रेटरी जनरल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत टीएमसी द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर उन 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

इस दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सवाल नोटिस जारी करने का नहीं है, सवाल एक तय समय-सीमा के अंदर कार्यवाही पूरी करने का है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इन 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और बाद में नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया में शामिल हो गए। अभिषेक बनर्जी का तर्क है कि उनके इस आचरण के कारण संविधान के दलबदल-रोधी प्रावधानों के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

## पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अमेरिका को की थी लीक

### पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा खुलासा

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान ने पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि इस ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान की ओर से अमेरिका को लीक की गई होगी। पूर्व सीडीएस ने स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर पूरी तरह द्विपक्षीय बातचीत हुई थी और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि भारत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कैसे कर दिया।

पूर्व सीडीएस ने बताया कि गत वर्ष 29 अप्रैल को आतंकवादी ठिकानों को सटीक निशाना बनाने का अहम फैसला लिया गया

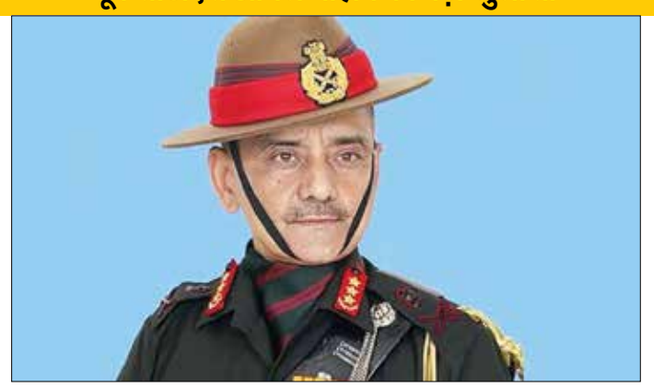

था और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेना पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। संघर्ष विराम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच आपसी सहमति से समय तय किया गया था। फोन पर बातचीत के बाद शाम पांच बजे का समय निर्धारित हुआ था, जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सीजफायर केवल दो सैन्य अधिकारियों के बीच की आपसी समझ का परिणाम था। जब उनसे यह सवाल किया गया कि यह गोपनीय जानकारी अमेरिका तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सूचना भारतीय पक्ष की तरफ से बिल्कुल लीक नहीं की गई थी। उन्होंने अंदेशा जताया कि यह जानकारी निश्चित तौर पर दूसरे पक्ष यानी पाकिस्तान की तरफ से ही लीक हुई होगी। इसके अलावा, पूर्व सीडीएस ने किराना हिल्स पर किए गए हमलों की अटकलों पर भी विराम लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों वाले क्षेत्र किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया गया था। उन्होंने समझाया कि हमलों से पहले सरगोधा क्षेत्र में कई ड्रोन भेजे गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य वहां के रडार का पता लगाना था। हवा में लंबे समय तक मंडराने के बाद यदि इन ड्रोनों को कोई लक्षित स्थान नहीं मिलता है, तो वे नीचे उतरकर टकरा जाते हैं। संभवतः इसी प्रक्रिया के दौरान कोई ड्रोन किराना पहाड़ियों से टकरा गया होगा, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने गलत तरीके से प्रचारित किया था।

## 5 सितंबर को इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक मार्च का ऐलान

### सीजेपी के नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
जेन-जी से जुड़े एक हालिया कान्क्लेव में कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों मुख्य चेहरे अभिजीत दीपक, आशुतोष रांका और सौरव दास शामिल हुए। इस दौरान जब अभिजीत दीपक से सवाल किया गया कि क्या वे दिल्ली केवल बवाल मचाने आते हैं और उन्होंने फिर से मार्च का ऐलान क्यों किया है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाना है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है।

दीपके ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के लिए एक करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि सांसद और विधायकों की खरीद-फरोख्त में 50 से 100 करोड़ रुपये आसानी से खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की मदद करने में कंजूसी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी प्रमुख मांग छात्रों पर दर्ज की गई एफआईआर को तुरंत वापस लेने की है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने शिक्षा से जुड़े अधिकार मांग रहे थे, न कि किसी से वोट। कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए दीपके ने बताया कि आगामी 5 सितंबर को इंडिया गेट 1.0 के तहत वे इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक शांति मार्च निकालेंगे। उन्होंने बताया कि वे आकांक्षा चतुर्वेदी के परिवार से मिले थे, जिनके पिता को बेटी की मौत के सदमे में पैरालिसिस और हार्ट अटैक आ गया था। उस परिवार ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था और अब वे गहरे आर्थिक संकट में हैं। चर्चा के दौरान आशुतोष रांका से जयपुर में हुई घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे वोट मांगने नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। राजस्थान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी यदि राजधानी के पास स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहे हैं, तो यह शर्मनाक है। हिंसा के डर से जुड़े सवाल पर अभिजीत दीपक ने तंज कसते हुए कहा कि वे और रांका पहले ही पुलिस या विरोध के दौरान पिट चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वे आगे भी प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार हैं। सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के रवैये पर बात करते हुए कहा कि मंत्रियों के वादों के बावजूद युवाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआईआर की सूची मांगने और केंद्र सरकार के वकीलों द्वारा इस पर स्पष्ट प्रतिबद्धता न दिखाने के कारण उन्हें युवाओं के हित में यह बड़ा कदम उठाना पड़ा है।

## जनता ने जिस सीएम को नकारा है उन्हें वही पसंद है : पूनावाला

### -शहजाद का अभिजीत दीपके पर पलटवार

**नई दिल्ली, एजेंसी।**
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा कुछ मुख्यमंत्रियों को देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं की सूची में शामिल करने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे शहजाद पूनावाला ने अभिजीत दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पर तीखा हमला बोला है। पूनावाला ने कहा है कि दीपके को जिन मुख्यमंत्रियों को अच्छे लगते हैं, उन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने सीजेपी को फ्रॉड पार्टी करार देते हुए दीपके के चुने गए तीन मुख्यमंत्रियों के चयन पर गंभीर सवाल उठाए।

हाल ही में एक कार्यक्रम में अभिजीत दीपके ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) के नेता एमके स्टालिन और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में शामिल किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा, ये तीनों ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें

उनकी जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सीजेपी को वो सीएम अच्छे लगते हैं, जिन्हें जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने तंज कसा कि कॉकरोच जनता पार्टी में से जनता को हटाकर सिर्फ कॉकरोच पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि जनता का निर्णय कुछ और रहा है। पूनावाला ने अभिजीत दीपके के दावों का खंडन करते हुए तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर एमके स्टालिन के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन ने तमिलनाडु की नहीं, बल्कि अपने परिवार की अर्थव्यवस्था और अपने बेटे का उदय किया। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि स्टालिन के पांच सालों के कार्यकाल में तमिलनाडु का कर्ज 2021 में 4.86 लाख करोड़ से बढ़कर 9.52 लाख करोड़ हो गया था। पूनावाला ने टिप्पणी की, जितना 60-70 सालों में बढ़ा, उतना पांच सालों में स्टालिन ने बढ़ाया। ये अच्छा कर रहे थे इकोनॉमी को।

केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ पर भी पूनावाला ने आपत्ति जताई। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि केरल की आबादी साढ़े तीन करोड़ थी, और आंकड़ों के अनुसार वहां 71 हजार मौतें हुईं। इसकी तुलना में, उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ थी और वहां कोविड से जुड़ी मौतें 23 हजार 700 हुईं थीं। पूनावाला ने इसे कुप्रबंधन बताते हुए कहा, छोटा राज्य होने के बावजूद केरल में यूपी से ज्यादा मौतें हुईं। ये था केरल हेल्थ मॉडल।

# अन्नपूर्णा योजना पर ममता के सवाल, सुवेंदु ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

**कोलकाता, एजेंसी।**
पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। इस बार विवाद की वजह अन्नपूर्णा योजना को लेकर उठे सवाल हैं। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर योजना के लाभ को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए उनके आरोपों का जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने राज्य की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है।

ममता बनर्जी ने सोमवार दोपहर सोशल मीडिया लाइव के दौरान अन्नपूर्णा योजना को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और आरोप लगाया कि लाभार्थियों के चयन में जाति को आधार बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने की अपील की, जिन्हें कथित तौर पर योजना का लाभ नहीं मिला है। ममता ने कहा कि वह लोगों के साथ पहले भी खड़ी थीं और आगे भी रहेंगी।

सुवेंदु ने बताए लाभार्थियों के आंकड़े

ममता के आरोपों पर सुवेंदु अधिकारी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 45 लाख 64 हजार 472 लाभार्थियों को फायदा मिला है। उनके मुताबिक, इनमें करीब 19 लाख 20 हजार मुस्लिम लाभार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि योजना का लाभ देते समय जाति और धर्म को आधार नहीं बनाया जाता।उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की करीब एक लाख महिलाओं को योजना के तहत लाभ मिलने का भी दावा किया। नंदीग्राम के एक ब्लॉक का उदाहरण देते हुए अधिकारी ने कहा कि वहां दो हिंदू और 52 मुस्लिम परिवारों को आवास के लिए आर्थिक सहायता दी गई। उनके मुताबिक, सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले।

सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि अन्नपूर्णा योजना को लेकर सरकार के पास करीब 4.5 लाख शिकायतें पहुंची हैं। इनमें योजना का लाभ मिलने और लाभ से वंचित रहने, दोनों तरह की शिकायतें शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि योजना का उद्देश्य सभी पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना था तो शुरुआत में इसे 25 से 60 वर्ष की आयु सीमा तक क्यों सीमित किया गया। उन्होंने बताया कि शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। आंकड़े गिनाने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सोशल मीडिया लाइव को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ममता दोपहर में सोशल मीडिया पर ही रहती हैं और उन्हें सड़कों पर निकलने की जरूरत नहीं है।उन्होंने ममता की हालिया राजनीतिक गतिविधियों पर भी कटाक्ष किया और बारुईपुर तथा हलीशहर में उनके कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए खेल के उदाहरण दिए।

## संघ प्रदेश श्रीडी में विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव में प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जिला प्रशासन दादरा नगर हवेली द्वारा रेड क्रॉस भवन सिलवासा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन दादरा नगर हवेली कलेक्टर द्वारा किया गया। इस अवसर पर दादरा नगर हवेली प्रशासन के विभिन्न अधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सिलवासा नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा नगर परिषद के पार्षदगण उपस्थित रहे। शिविर में विभिन्न क्षेत्रों से आए रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया। रक्तदाताओं की इस सराहनीय भागीदारी ने समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी एवं मानवीय संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर 69 बार रक्तदान करने वाले शैलेन्द्र सिंह, 60 बार रक्तदान करने वाले योगेश सुलाखे तथा 51 बार रक्तदान करने वाले बिस्वश्वरंजन मुदुली का सम्मान किया गया। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे आगे बढकर नियमित रूप से रक्तदान करें। रक्तदान एक अत्यंत महान एवं पुनीत सामाजिक कार्य है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी रक्तदाताओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया तथा समाज के अन्य लोगों से भी रक्तदान जैसे नेक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।

## दीव के मुस्लिम समुदाय ने मनाई ईद-ए-मिलादउन-नबी

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दीव, 26 अगस्त। दीव में मुस्लिम समाज द्वारा पैगंबर हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद-ए-मिलादउन-नबी मनाई गई। इस मौके पर दीव जिले में मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में बडी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर दीव कलेक्टर राहुल देव बुरा, पुलिस अधीक्षक राम कृष्ण सरन, डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा, एसडीपीओ राहुल बल्हारा, मामलतदार धर्मेश दमणिया, दीव नगरपालिका अध्यक्ष हरेश कापडिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल वोरा और अन्य महानुभावों ने शामिल होकर मुस्लिम समुदाय को ईद-ए-मिलादउन-नबी की हार्दिक बधाई दी।

## दमण में जश्न-ए-ईद मिलाद का बड़ी अकीदत के साथ निकाला गया जुलूस

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 26 जनवरी। दमण में आज 12 रबी-उल-अव्वल शरीफ के पुरनूर मौके पर अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से जश्न-ए-ईद मिलाद के मुबारक जुलूस निकाले गए। आशिकान-ए-रसूल ने अपनी-अपनी मस्जिदों, मदरसों और मोहल्लों से जुलूस निकाले। जिनमें प्रमुख रूप से खानदेश सुन्नत जमात, दारुल उलूम कादरिया अशरफिया गरीब नवाज, आशिक-ए- शालिमुल्लाह रिफाई कमेटी, देवका सुन्नी मुस्लिम सुन्नत जमात, अनवार-ए-रज़ा मस्जिद, मोटी दमण, खारावाड सुन्नत जमात, उत्तर प्रदेश मुस्लिम जमात, दमण मेमन जमात की जमातें और कमेटियां शामिल रहीं। जश्न-ए-ईद मिलाद का जुलूस बड़ी अकीदत, मोहब्बत और जोश-ओ-खरोश के साथ निकाले गए। इस मौके पर दमण मुस्लिम एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदर जनाब जाकिरहुसैन पीरवाला का फूल-मालाओं से इस्तकबाल किया गया और शॉलपोशी की गई। खानदेश सुन्नत जमात का जुलूस जब अपने मदरसे से निकलकर घांचीवाड़ की गलियों से होते हुए राणा स्ट्रीट पहुंचा तो वॉर्ड नंबर 4 की काउंसलर के सुपुत्र और दमण राणा समाज के युवा अध्यक्ष रवि नरेन्द्र राणा ने जुलूस का स्वागत किया। उन्होंने सभी को ईद मिलाद की मुबारकबाद दी और हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। इस मौके पर उनकी जानिब से शरबत और पानी की विशेष व्यवस्था की गई थी। खानदेश सुन्नत जमात, दारुल उलूम कादरिया अशरफिया गरीब नवाज, अनवार-ए-रजा मस्जिद मोटी दमण, आशिक-ए-शालिमुल्लाह रिफाई कमेटी, उत्तर प्रदेश मुस्लिम जमात और दमण मेमन जमात के जुलूस अपनी-अपनी मस्जिदों/मदरसों से निकलकर रजा मस्जिद, घांचीवाड, नानी दमण पर एक जगह जमा हुए। वहां से एक विशाल जुलूस की शक्ल में बस स्टैंड, मेन रोड, जापाबार, खाटकीवाड़, कवि खबदार रोड, नानी दमण जेटी होते हुए अपनी-अपनी मस्जिदों/मदरसों में वापस पहुंचा, जहां सलातो-सलाम पढ़कर नियाज़ तकसीम की गई और जुलूस का इख्तेताम किया गया। देवका सुन्नी मुस्लिम सुन्नत जमात का जुलूस पूरे देवका और तड़वाड़ क्षेत्र में निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान-ए-रसूल ने शिरकत की। जुलूस के बाद जमात की जानिब से आम लंगर का एहतमाम किया गया। इसी तरह खारावाड सुन्नत जमात का जुलूस पूरे खारावाड में निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस मस्जिद पर वापस पहुंचा, जहां मकतब के बच्चों ने नात शरीफ और सलातो-सलाम पेश किया, उसके बाद नियाज तकसीम हुई। इस मुबारक मौके पर दमण मुस्लिम समाज के कई जिम्मेदारान और उलमा-ए-किराम मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से जाकिरहुसैन पीरवाला (सदर, दमण मुस्लिम एसोसिएशन), बदरुद्दीन बैग, असरार माथव, बहाउद्दीन बैग, नूरू शेख, मौलाना फारूक खान पठान, अब्दुल कादिर नाखुदा, मोइनुद्दीन पीरवाला, जुबैर कारा, मौलाना सैफुर्रज़ा, मौलाना असलम बरकाती, सैयद जैदी अशरफ, सैयद सरवर कादरी, सोहेल खान पठान, नदीम मस्तान सहित सैकड़ों अकीदतमंद शामिल हुए। पूरा जुलूस अमन व शांति के साथ मुकम्मल हुआ। इस दौरान प्रशासन और पुलिस का सहयोग सराहनीय रहा। आखिर में मुल्क में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई।

## बिरसा मुंडा स्कूल कैंपस में जोन स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 26 जनवरी। शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के अंतर्गत बिरसा मुंडा स्कूल कैंपस खानवेल में जोन स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मराठी माध्यम के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के 6 स्कूलों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों से विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान से जुडे कई ज्ञानवर्धक सवाल पूछे गए। इस कडे मुकाबले में सिलवासा एमएम उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक के छात्रों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं खानवेल एमएम उच्चतर माध्यमिक के छात्रों को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में गुजराती और इंग्लिश हाईस्कूल के प्रिंसिपल हसमुख पटेल, बिरसा मुंडा इंग्लिश मीडियम स्कूल के असिस्टेंट हेडमास्टर अजयभाई और खानवेल ब्लॉक के विज्ञान और गणित विषय के बीआरपी देवीदास जगदेव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस सफल कार्यक्रम का आयोजन सीआरसी कोर्डिनेटर बिमलसिंह राजपूत द्वारा किया गया। प्रतियोगिता को सफल बनाने में विभिन्न विद्यालयों से आए सभी शिक्षकों का सराहनीय सहयोग मिला।

## विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुधनी में हुई नौका दौड़ प्रतियोगिता

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव में प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन दादरा नगर हवेली द्वारा आज पैनोरमिक व्यू वाघचौडा दुधनी रोड में भव्य नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर पालिका के काउंसिलरों तथा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नौका दौड़ प्रतियोगिता में दादरा नगर हवेली के विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों से नाविकों एवं नाव सवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया तथा कौंचा एवं दुधनी के प्राकृतिक एवं मनोरम वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों और उपस्थित दर्शकों में विशेष उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया तथा संघ प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विकास की उपलब्धियों के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, खेलकूद एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी रहा। दुधनी में आयोजित इस नौका दौड़ प्रतियोगिता ने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय प्रतिभा को एक मंच प्रदान किया तथा विकास के साथ जनभागीदारी और सामुदायिक भावना के संदेश को भी सशक्त बनाया।

## दमण बाल भवन में नारियल पूर्णिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 26 जनवरी। बाल भवन बोर्ड दमण द्वारा आज नारियल पूर्णिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत पूजा थाली सजावट एवं राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दमण की विभिन्न विद्यालयों के लगभग 100 बच्चों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आनेवाले बच्चों को सर्टिफिकेट एवं गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया गया।

## दीव में डीजल में मिलावट की शिकायतों के बाद प्रशासन ने उठाए सख्त कदम

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दीव, 26 अगस्त। दीव में डीजल में मिलावट की शिकायतों के बाद दीव प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। दीव जिला कलेक्टर राहुल देव बुरा और डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा के मार्गदर्शन में मामलतदार के नेतृत्व में दीव के कई पेट्रोल पंपों पर जाँच की गई। जाँच के दौरान क्लर्क रामजीभाई ने दीव जिले के पेट्रोल पंपों और वणाकबारा की दो फिशरीज सोसायटियों से डीजल के सैंपल लिये। सभी सैंपल नियमों के अनुसार सील किए गए और उन पर पेट्रोल पंप अधिकारी के हस्ताक्षर लिए गए। अब इन सैंपल को क्वालिटी और मिलावट की जाँच के लिए अधिकृत लैब में भेजा जाएगा। जाँच रिपोर्ट आने के बाद यदि डीजल में कोई मिलावट या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

**CHANGE OF NAME**

OLD NAME - ALKABEN NARANDAS MANGELA
**NEW NAME - ALKA PRALHAD AMBHIR**
ADDRESS - 6/214 , YOGESHWAR MANDIR ROAD, MANGELWAD, MOTI DAMAN 396220

**CHANGE OF NAME**

OLD NAME - NARANDAS MADHABHAI MANGELA
**NEW NAME - NARAN MADHABHAI MANGELA**
ADDRESS - 6/214 , YOGESHWAR MANDIR ROAD, MANGELWAD, MOTI DAMAN 396220

# शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा बेमानी

निर्मल रानी

**देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा,शिक्षण संस्थाओं की कमी व दुर्दशा तथा परीक्षा व्यवस्था में होने वाली धांधलियों व पेपर लीक जैसे मुद्दों ने देश के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। इससे घबराई सरकार कहीं स्कूल की वीडिओ ग्राफी करने पर रोक लगा रही है तो कहीं शिक्षण संस्थाओं की हकीकत को उजागर करने वालों पर सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। और कहीं सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाएं दिखाने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। परन्तु इस बीच कुछ जगहों से सकारात्मक खबरें भी आनी शुरू हुई हैं।**

हमारे देश में पिछले एक दशक से भारत को विश्वगुरु बनाने का ढोल पीटा जा रहा है। इसी विमर्श के समानांतर इस समय देश में शिक्षा को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अतः इसी सन्दर्भ में यह सवाल भी जरूरी हो गया है कि क्या शिक्षा के बिना या शिक्षित हुये बिना भी भारत विश्वगुरु बन सकता है ? नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दशक में देशभर में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल या तो पूरी तरह बंद किये जा चुके हैं या उनका अन्य स्कूलों में विलय कर दिया गया है। यूडीआईएसई अर्थात यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के हालिया आंकड़े व नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, एक साल के भीतर देश भर में 4,791 स्कूल बंद हुए हैं। इसकी वजह से शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी निजी स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा गरीबों की पहुँच से दूर हो चुकी है। और जो स्कूल चल भी रहे हैं उनमें से अधिकांश की हालत किसी से छुपी नहीं है। यहाँ अक्टूबर 2022 की गुजरात की उस घटना का जिक्र भी प्रासंगिक है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के अडालज में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ के दौरान अस्थाई रूप से बनाये गये एक मॉडल क्लासरूम में बच्चों के साथ बैठे नजर आये थे। सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य गुजरात के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और डिजिटल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना बताया गया था। उस समय विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि प्रधानमंत्री जिस क्लासरूम में बैठे थे, वह एक अस्थायी या कृत्रिम क्लासरूम था। संबंधित तस्वीरों का हवाला देते हुए दीवारों और खिड़कियों के पेंटिंग के स्टिकर होने का दावा किया गया था और इसे फोटो शूट करार दिया था। परन्तु अधिकारियों ने इसके जवाब में यह कहा था कि यह आगामी डिजिटल स्मार्ट स्कूलों का एक मॉडल प्रस्तुतीकरण था जो यह प्रदर्शित करने के लिए था कि भविष्य के क्लास रूम कैसे नजर आयेंगे। तो सवाल यह है कि गत चार वर्षों में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत अब तक उन मॉडल क्लासरूम की तरह देश में कितने आधुनिक क्लासरूम व आधुनिक स्कूल बनाये गये?

दूसरी ओर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने 25 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कई अन्य विदेशी मेहमान और प्रतिनिधिमंडल भी आ चुके हैं। समय-समय पर विभिन्न देशों के शिक्षाविद, राजनयिक और प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बुनियादी संरचना, कक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का निरीक्षण करने दिल्ली आते रहे हैं। क्या इसी तरह के आधुनिक सरकारी स्कूल पूरे देश में संचालित नहीं हो सकते? क्या वजह है कि देश के अधिकांश राज्यों में अनेकानेक सरकारी स्कूल भवन जर्जर हैं ? कहीं स्कूल में भैंसों के तबेले हैं तो कहीं पेड़ के नीचे व खुले आसमान तले क्लास लगाई जा रही है। कहीं क्लासरूम नहीं। कहीं अध्यापक नहीं तो कहीं बिजली व पीने का पानी नहीं तो कहीं शौचालय नहीं। कहीं बच्चे रोज नदी पार कर स्कूल आते जाते हैं तो कहीं कीचड़ और दलदल भरी गड्ढेदार सड़कों से गुजर कर स्कूल आना जाना होता है। यदि देश की सरकारें शिक्षा के प्रति गंभीर होतीं और उनका भारत को विश्वगुरु बनाने का ढिंढोरा महज ढोल पीटना न होता तो आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले को महाराष्ट्र में शिक्षा पर घटते बजट और सरकारी मराठी माध्यम के स्कूलों के बंद होने पर गहरी चिंता जताते हुये यह न कहना पड़ता कि नासिक कुंभ मेले के लिए लगभग रू.32,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट तय किया गया है। अगर इस राशि का मात्र 0.1% यानी लगभग रू.32 करोड़ भी शिक्षा पर खर्च किया जाता, तो राज्य के 100 से 125 बंद हो रहे मराठी स्कूलों को बचाया जा सकता था। आखिर जस्टिस प्रसन्ना को क्यों कहना पड़ा कि देश में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा का बजट बढ़ने के बजाय घट रहा है, जो पिछले कई वर्षों से 13% के आंकड़े को भी नहीं छू सका है । उन्होंने गढ़चिरौली की एक घटना का उदाहरण भी दिया जहां जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण फर्श पर सोने की वजह से तीन छात्राओं की सांप के काटने से मौत हो गई थी। जस्टिस प्रसन्ना ने यह भी बताया कि उन्होंने स्वयं 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जिला परिषद के मराठी मीडियम स्कूल से की थी, जिसने उनके करियर में कभी बाधा नहीं डाली बल्कि उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है।

देश में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा,शिक्षण संस्थाओं की कमी व दुर्दशा तथा परीक्षा व्यवस्था में होने वाली धांधलियों व पेपर लीक जैसे मुद्दों ने देश के युवाओं को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। इससे घबराई सरकार कहीं स्कूल की वीडिओ ग्राफी करने पर रोक लगा रही है तो कहीं शिक्षण संस्थाओं की हकीकत को उजागर करने वालों पर सत्ता समर्थित गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है। और कहीं सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूल की अव्यवस्थाएं दिखाने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। परन्तु इस बीच कुछ जगहों से सकारात्मक खबरें भी आनी शुरू हुई हैं। जैसेकि राजस्थान के रामपुरा के उस स्कूल का नवनिर्माण करने का फैसला किया गया है जहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता के समर्थक गुंडों ने मारपीट की थी। यह स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था। स्कूल की इमारत जर्जर होने के कारण एक स्थानीय ग्रामीण ने अपनी निजी जगह दी हुई है, इसी जगह भैंसों का चारा भी रखा जाता है और बच्चे भी पढ़ते हैं। पंजाब से भी खबर है कि सरकार ने स्कूलों के अनेक नए भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन ग्रीनफील्ड भवनों का निर्माण मौजूदा जमीनों से परे अन्य खाली जमीनों पर नए सिरे से किया जाएगा। हरियाणा में भी शिक्षा मंत्री द्वारा सरकारी स्कूल्स का औचक निरीक्षण कर विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लेने व विद्यार्थियों से संवाद करने की खबर है। Gen Z और युवा पीढ़ी के आंदोलन से ही सही परन्तु शायद अब सत्ताधीशों को यह बात समझ आने लगी है कि शिक्षित राष्ट्र के बिना विश्व गुरु की अवधारणा पूरी तरह बेमानी है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

## संपादकीय

### ज़हर बांटते उद्योग

कुछ उद्यमी मुनाफे की अंधी हवस में इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को साफ किए बिना ही जलधाराओं में बहा देते हैं। जबकि उनकी नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी फैक्ट्रियों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण व नदी-नालों को प्रदूषित न करें। हिमाचल प्रदेश स्थित बद्दी-नालागढ़ इलाके में कई औद्योगिक इकाइयां नदियों में जहरीले रसायन लगातार बहाती रही हैं। यह प्रदूषणकारक कचरा सिरसा नदी में बहा दिया जाता है, जो कालांतर सतलुज नदी में चला जाता है। यही वजह है कि आज सतलुज का प्रदूषित पानी जो चेतावनी दे रहा है उसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं। इसी आने वाले संकट के मद्देनजर ही बद्दी-नालागढ़ इलाके की अज्ञात औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो मामले की गंभीरता को ही दर्शाता है। निस्संदेह, यह संकट कोई नई समस्या नहीं हैं। जो हमारे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम व कानूनों को लागू करने में तंत्र की बार-बार होने वाली विफलता को ही दर्शाता है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र से होने वाले औद्योगिक प्रदूषण के प्रामाणिक रिकॉर्ड कई सालों से मौजूद हैं। दरअसल, यह जहरीला कचरा इस औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाली सिरसा नदी में डाल दिया जाता है। सिरसा नदी इन प्रदूषक तत्वों को आगे की ओर बहा ले जाती है। कालांतर यह सतलुज नदी में जाकर मिल जाता है। इस बाबत कई बार जांच भी की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में बिना ट्रीट किए गए रसायनयुक्त कचरे व ठीक से ट्रीट न किए गए कचरे के बारे में उल्लेख किया गया है। ट्रिब्यूनल ने नियमों का पालन न करने वाली इकाइयों तथा ट्रीटमेंट सिस्टम की खामियों की ओर इशारा किया है। दरअसल, फार्मास्युटिकल प्रदूषण की समस्या बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि पारंपरिक ढंग से ट्रीटमेंट करने वाले सिस्टम से सक्रिय फार्मास्युटिकल तत्व और एंटीबॉयोटिक के अवशेष पूरी तरह से नहीं हट पाते हैं। दरअसल, हाल के प्रकरण से एक और परेशान करने वाली विरोधीभासी बात सामने आई है। इस बाबत सूचना मिली थी कि रोपड़ हेडवर्क्स पर भारी मात्रा में जमा कचरे को नदी के बहाव की दिशा में बेफिक्री से छोड़ दिया गया। निस्संदेह, यदि यह कचरा नुकसानदायक था, तो इसे नदी में छोड़ने से समस्या महज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित ही हुई है। कायदे से हेडवर्क्स में जमा कचरे की वैज्ञानिक तौर-तरीकों से निगरानी की जानी चाहिए थी। सही मायने में प्रदूषणकारक कचरे को ठिकाने लगाने से पहले उसके सैंपल लेकर उसकी जांच-पड़ताल की जानी जरूरी थी। निश्चित रूप से यह संकट बड़ा है और तत्काल इसका समाधान किया जाना चाहिए था। वास्तव में इस मामले को हिमाचल बनाम पंजाब के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि दोनों सरकारें मिलकर प्रदूषण फैलाने वाले कचरे का वास्तविक स्रोत तलाशें क्योंकि अभी तक कचरे के असली स्रोत का पता नहीं चल सका है।

## चिंतन-मनन

### कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है जीव

ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीवविशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप-पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। चूंकि इस प्रकार वह आत्मा देहांतरण कर जाता है, अत उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मो का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत कर्मो के सारे फल बदल जाते हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्वों- ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शात हैं, कर्म शात नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान हैं- भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं- जब वे इस भौतिक वि में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे भगवद्गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मष-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य-जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित (दूषित) नहीं हैं। भगवद्गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है।

# आतंकवाद के लिए खाद पानी है नशीले द्रव्यों की तस्करी!

मनोज कुमार अग्रवाल

भारत में नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी देश की आंतरिक सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अत्यंत गंभीर संकट बन चुकी है। भौगोलिक रूप से भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों - पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान) और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के बीच स्थित है। इस संवेदनशील स्थिति के कारण देश में सीमा पार से बड़े पैमाने पर अवैध नशीले पदार्थों की आमद हो रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी में भारत की भौगोलिक स्थिति भी खासा जिम्मेदार है पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार से सटी खुली और जटिल जमीनी सीमाएं निगरानी के लिए एक बड़ी चुनौती है ।तस्करों द्वारा गुजरात और दक्षिणी राज्यों के विशाल तटीय क्षेत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है ।अब नशे के सौदागर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं डार्कनेट क्रिप्टो करेंसी और सीमा पार से ड्रग्स गिराने के लिए ड्रोन का बढ़ता प्रयोग खतरा बढ़ा रहे हैं वहीं पारंपरिक अफीम-गांजे के स्थान पर हेरोइन, कोकीन और मेथामफेटामाइन जैसे घातक रसायनों सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता चलन भी समस्या बन रहा है।

आपको बता दें कि देश में नशे और नशीले पदार्थों की तस्करी ने एक बार फिर केन्द्र और राज्यों की सरकारों को स्तब्ध किया है। नशीले पदार्थों की यह तस्करी का बड़ा हिस्सा पड़ोसी देश पाकिस्तान के माध्यम से सीमा पार से ड्रोनों के जरिये किया जाता है। नशे को लेकर किये गये एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार पाकिस्तान एक प्रकार से नशीले पदार्थों के भण्डारण का केन्द्र बन गया है जहां से इन पदार्थों का बहुत बड़ा भाग भारत के पंजाब प्रांत में ड्रोनों के जरिये खपाया जाता है। भारत से फिर यह सामान तस्करी के जरिये कई अन्य देशों में भेजा जाता है जहां इसकी बड़ी मांग होती है। पाकिस्तान से भारत में पंजाब सीमा के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी यूं तो दशकों पूर्व से की जाती आ रही है। कभी नावों के माध्यम से, कभी सुरंगों के जरिये पाकिस्तानी पंजाब के सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम और हेरोइन की तस्करी की जाती रही है। तथापि, आजकल नावों का कार्य ड्रोनों से लिया जाने लगा है। ड्रोनों के जरिये पाकिस्तानी सीमा-पार से भारतीय पंजाब में अफीम, हेरोइन के साथ हथियारों की खेप भेजना जैसे आम बात हो गई है वैसे तो नशे के लिए अफीम, चरस, कोकीन आदि अनेकानेक द्रव्यों एवं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है किन्तु वर्तमान में हेरोइन सर्वोत्तम नशीला पदार्थ बन गया है। हाल ही में एक और बड़ा खतरनाक नशीला पदार्थ आईस भी बड़ी चर्चा में आया है। विगत कई वर्षों से हेरोइन की तस्करी और इसके सेवन की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका बड़ा प्रमाण इस एक तथ्य से मिल जाता है कि इन दिनों सीमाओं पर विशेष सुरक्षा चौकसी होने के बावजूद तस्करी से बरामद होने वाली खेपों की संख्या और मात्रा बढ़ गई है। इसके लिए तस्करों द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाने लगा है। सीमा सुरक्षा बलों की निरन्तर चौकसी और सतर्कता के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले पांच वर्षों में पंजाब सीमा पर ड्रोन तस्करी की घटनाएं बढ़ कर तीन से 304 प्रति वर्ष तक हो गई हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में स्थितियों की गम्भीरता को पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस एक कठोर टिप्पणी से बेहतर समझा जा सकता है कि नशे का यह सम्पूर्ण कारोबार महज एक आपराधिक कार्य मात्र नहीं रह गया, अपितु राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

यूं तो नशे के सेवन और नशीले पदार्थों की तस्करी से गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रदेश बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं किन्तु पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्या एक गम्भीर संकट के रूप में उभर रही है। पंजाब सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत प्रदेश का पुलिस तंत्र युवाओं को इस महारोग से बचाने के लिए भरसक यत्न कर रहा है किन्तु यह समस्या एक ऐसे बिगड़ैल घोड़े के समान हो गई है कि जिसकी नाक में आसानी से नकेल नहीं डाली जा सकती।

अभी हाल में अमृतसर के थाना लोपोके क्षेत्र में सीमा पार से आई लगभग 180 करोड़ रुपये की 19 किलो हेरोइन के साथ महिला सहित तीन तस्करों को हिरासत में लिया गया। नशा तस्करी में यह भी एक नई प्रवृत्ति सामने आई है कि अवयस्क बालकों को थोड़े से लालच के वशीभूत इस गैर-कानूनी कार्य में शामिल किया जा रहा है। महिलाओं एवं बच्चों की शमूलियत से इस अवैध क्रिया-कलाप को एक नया मोड़ मिला है। पिछले कुछ समय में पंजाब में पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े कई अवयस्कों और महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। प्रदेश सरकार ने अपने ऑपरेशन प्रहार के दौरान लगभग 4000 तस्करों-गैंगस्टरों को गिरफ्तार भी किया है। इतने बड़े स्तर पर तस्करों की गिरफ्तारी, इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन की खेपों की बरामदगी से तस्करी पर काबू पाये जाने की सम्भावना बनती है, किन्तु इतनी बड़ी बरामदगी और बड़े स्तर पर युवाओं और अव्यवस्कों की भागीदारी से इस कारोबार की भीषणता भी जाहिर होती है। पंजाब सरकार के प्रहार अभियानों और प्रदेश के पुलिस तंत्र की सक्रियता से बेशक प्रदेश के लोगों के मन में आशा और विश्वास की एक लकीर उपजते दिखाई देती है, किन्तु हम समझते हैं कि लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाना भी बहुत जरूरी है। पुलिस तंत्र की सक्रियता कागजों में भी हो, किन्तु धरातल पर उसे दिखाई भी अवश्य देना चाहिए। कानून के हाथ लम्बे होते हैं, किन्तु ये हाथ अपराधियों और तस्करों के गिरेबान तक पहुंचने भी तो चाहिएं। कुछ भी हो अथवा कुछ भी किया जाए, देश को नशीले पदार्थों की तस्करी की इस लानत से मुक्ति मिलनी चाहिए।

देश की कामकाजी आबादी खासकर युवा और कालेज छात्र छात्राएं स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आकर मानसिक और शारीरिक रूप से पंगु हो रहे हैं।नारको-टेररिज्म जड़ जमा रहा है। ड्रग्स की तस्करी से होने वाली अवैध कमाई का इस्तेमाल सीधे तौर पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों और उग्रवाद की फंडिंग में किया जाता है। नशे की दैनिक तलब पूरी करने के लिए युवा चोरी, लूटपाट और संगठित अपराधों के रास्ते पर जा रहे हैं। अवैध काले धन और हवाला कारोबार के कारण देश की मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है।

ऐसा नहीं है कि सरकार को नशीले द्रव्यों की तस्करी और उसके कारण हो रही बबार्दी का भान नहीं है सरकार ने इस ओर नियंत्रण के लिए की प्रभावी कदम उठाए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और नशे के दुष्परिणामों से युवाओं को आगाह किया है। भारत सरकार ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. गृह मंत्रालय ने अगले 3 वर्षों में देश को पूरी तरह ड्रग-मुक्त बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 - 2029 जारी किया है।हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूएई से ?1,000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह बसोया का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण कराया गया है।डिजिटल कवच बनाया गया है नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 मानस शुरू की गई है, जिस पर लोग सीधे तस्करी की गुप्त सूचनाएं दे सकते हैं। तस्करों की संपत्तियों को कुर्क करने और पीआइटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत आदतन अपराधियों को बिना जमानत जेल में रखने की कार्रवाई तेज कर दी गई है अभी और अधिक असरदार कारवाई और सख्ती की जरूरत है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

# यूपीआई@10: भुगतान की दुनिया में भारत का नया अध्याय

सुनील कुमार महला

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा विकसित यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की एक तत्काल डिजिटल भुगतान प्रणाली है। सरल शब्दों में कहें तो यह वह माध्यम है, जिसके माध्यम से मोबाइल फोन से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत में यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को तत्कालीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( आरबीआई) गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने मुंबई में लॉन्च किया था। हालाँकि, आम लोगों के लिए यूपीआई सेवाएँ अगस्त 2016 से व्यापक रूप से उपलब्ध हुईं। इस साल यानी कि वर्ष 2026 में यूपीआई ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान को पूरी तरह बदल दिया है।सच तो यह है यूपीआई आज भारत के दैनिक डिजिटल भुगतान तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज यूपीआई का उपयोग हर कहीं पर दुकानों और बाजारों में सामान खरीदने, रेस्तरां व होटल के बिल चुकाने, ऑनलाइन खरीदारी, मोबाइल रिचार्ज, बिजली-पानी-गैस जैसे उपयोगिता बिलों के भुगतान, रेल-बस-विमान टिकट बुकिंग, स्कूल-कॉलेज की फीस, अस्पतालों में भुगतान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों तक डिजिटल लेन-देन में यूपीआई का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। यानी आज यूपीआई भारत के दैनिक जीवन में नकद भुगतान के एक आसान, तेज और सुविधाजनक डिजिटल विकल्प के रूप में स्थापित हो चुका है। बहरहाल, यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि अन्य देशों की तुलना में भारत का यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में असाधारण पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2026 में यूपीआई दुनिया के लगभग 49% रियल-टाइम भुगतान लेन-देन को संभाल रहा है, यानी दुनिया में होने वाले लगभग हर दो तत्काल डिजिटल भुगतानों में एक यूपीआई के माध्यम से होता है। भारत में इसकी मात्रा भी तेजी से बढ़ी है और वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई पर करीब 24,162 करोड़ लेन-देन हुए। मई 2026 में अकेले यूपीआई ने 23,201.93 मिलियन यानी लगभग 2,320 करोड़ लेन-देन किए, जिनका कुल मूल्य करीब रू.29.90 लाख करोड़ रहा। इस तुलना में भारत की खासियत यह है कि यूपीआई केवल बड़े शहरों या बड़े कारोबार तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले, ग्रामीण उपभोक्ता और आम नागरिक तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई अब 11 देशों में भी उपलब्ध है और वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण बन चुका है। अन्य शब्दों में कहें तो वर्ष 2016 में शुरू हुई यह व्यवस्था आज देश के कोने-कोने तक पहुंच चुकी है। पहले जहां डिजिटल भुगतान सीमित था, वहीं अब चायवाले, सब्जीवाले, छोटे दुकानदार और आम लोग भी आसानी से यूपीआई से पैसे ले-दे रहे हैं। एक दशक में यूपीआई लेन-देन में हुई भारी वृद्धि इसकी लोकप्रियता और लोगों के भरोसे को दिखाती है।यूपीआई से बैंकिंग आसान, तेज और सुविधाजनक हुई है। लोगों को नकदी निकालने के लिए बैंक जाने या लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत कम हुई है। आज पलभर में ही दूर बैठे व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, नकदी कम रखने से चोरी और लूट का जोखिम भी घटा है। डिजिटल भुगतान से लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में मदद मिली है।यूपीआई की सफलता के पीछे डिजिटल इंडिया अभियान और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार भी महत्वपूर्ण रहा है। देश में मोबाइल और ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ने से डिजिटल भुगतान आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यही कारण है कि दूसरे देश भी यूपीआई जैसी भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था में रुचि दिखा रहे हैं।हालांकि, अभी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। बैंक का सर्वर डाउन होना, अधिक ट्रैफिक के कारण भुगतान अटकना और गलती से गलत व्यक्ति को पैसे भेज देना जैसी समस्याएं लोगों के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इन समस्याओं का स्थायी समाधान जरूरी है। कुल मिलाकर, यूपीआई केवल पैसे भेजने और लेने का माध्यम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल प्रगति और आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमता का प्रतीक बन चुका है। दस साल की इसकी यात्रा बताती है कि जब तकनीक को आम आदमी की जरूरतों से जोड़ा जाता है, तो

वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। सच तो यह है कि यूपीआई के दस वर्ष केवल किसी डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता के दस वर्ष नहीं, बल्कि भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और डिजिटल परिवर्तन की एक उल्लेखनीय यात्रा हैं। इसने भुगतान को सरल, त्वरित और व्यापक बनाया तथा छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक को एक साझा डिजिटल मंच दिया। आज दुनिया के अनेक देश यूपीआई में रुचि ले रहे हैं और कई देशों में इसका उपयोग भी शुरू हो चुका है। यूपीआई ने साबित किया है कि भारत केवल डिजिटल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया को बड़े पैमाने पर अपनाने योग्य डिजिटल समाधान देने वाला देश भी है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता का अगला पड़ाव केवल लेन-देन की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, समावेशी और वैश्विक डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और मजबूत करना होगा।

## संक्षिप्त समाचार

### फिजी के मंदिरों में गूंज रहे भजन, सदियों की भारतीय परंपरा पर प्रवासियों को गर्व, विदेशी भी ले रहे प्रेरणा

**सुवा, एजेंसी।** भारत से हजारों किमी दूर प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप-राष्ट्र फिजी में भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी 19वीं सदी में गिरमिटिया मजदूरों के साथ वहां पहुंची थीं। श्रावण माह में यहां के मंदिर और सामुदायिक भवन में भक्ति-गीतों से सराबोर रहे। अगस्त में भजन जैमिंग 2026 कार्यक्रम युवाओं के लिए खास उत्साह का केंद्र रहा। यहां के राम मंदिर में अभी से रामलीला की तैयारियां भी की जाने लगी हैं। घरों में रामायण बजती है। सदियों की भारतीय परंपरा पर प्रवासियों को बेहद गर्व है और विदेशी भी परंपराओं के पालन की प्रेरणा ले रहे हैं। यहां के प्रमुख अखबार फिजी सन ने के मुताबिक, भजन जैमिंग कार्यक्रम में फिजी स्थित भारतीय-मूल के युवाओं ने पारंपरिक भजनों को समकालीन संगीत अंदाज में पेश किया। कार्यक्रम में बंदिश ग्रुप, सुकून ग्रुप और हनुमान चालीसा परिवार जैसी स्थानीय भजन-मंडलियों के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक के भारतीय छात्र संगठन ने भी प्रस्तुति दी। फिजी में बॉलीवुड मुख्य रूप से फिल्म शूटिंग, रेडियो शो, कंसर्ट्स और स्थानीय इंडो-फिजीयन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है।

### समृद्ध महासागर का हिस्सा- मिस्र के रेगिस्तान में कभी तैरती थीं विशाल शार्क मछलियां, क्रमिक रूप से हुआ विकास

**संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी।** मिस्र का रेगिस्तान करोड़ों साल पहले (लगभग 14.5 से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व) एक विशाल और समृद्ध महासागर का हिस्सा था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित अबू-तरतूर पठार पर शार्क के प्राचीन जीवाश्म और दांतों की खोज की है, जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह सूखा क्षेत्र कभी समुद्री जीवों और विभिन्न प्रजातियों की शार्क का गढ़ था। मिस्र में प्राचीन शार्क के जीवाश्मों की खोज से जु?ी यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका %क्रिटेशियस रिसर्च% में प्रकाशित हुई है ।मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान की चट्टानों से काहिरा विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी तारेक यासीन ने सात अलग-अलग शार्क प्रजातियों के दुर्लभ जीवाश्मों और शार्क के दांतों का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में मिलने वाले दांतों की आकृतियां अलग-अलग हैं। कुछ सुई जैसी नुकीली हैं तो कुछ चौड़ी और आरी के आकार की हैं, जो शिकार के अनुकूल थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्राचीन काल में यहां गहरी समुद्री धाराएं चलती थीं जो पानी की सतह पर पोषक तत्व लाती थीं। इससे प्लवक और छोटी मछलियों का विकास हुआ, जिस कारण यह पूरा क्षेत्र शार्क जैसे बड़े शिकारियों के लिए आदर्श स्थान था।

### सूडान में 59 हजार मौतों के बाद अमेरिका सख्त, ह्र से पूरे देश में हथियार बैन की मांग; बढ़ेगा दबाव

**संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी।** सूडान में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अरब और अफ्रीकी मामलों के वरिष्ठ सलाहकार मासाद बोलोस ने सोमवार को कहा कि प्रतिबंधों के जरिए युद्ध में शामिल दोनों पक्षों पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ाया जा सकता है। सूडान में चल रही इस लड़ाई में अब तक कम से कम 59 हजार लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। देश के कई हिस्से अकाल की चपेट में हैं। बोलोस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि सूडानी सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को मिल रहा वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक समर्थन संघर्ष को लंबा खींच रहा है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन मिस्र सूडान की सेना का खुलकर समर्थन करता रहा है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात पर ह्र विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने ऋस्न्र को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया है। इन आरोपों से इनकार करता रहा है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें सूडान के पूरे क्षेत्र में हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। मौजूदा प्रतिबंध मुख्य रूप से पश्चिमी दारफुर क्षेत्र तक सीमित है। प्रस्ताव में सूडान में सक्रिय सभी पक्षों पर प्रतिबंध लागू करने और ड्रोन व उनसे जुड़ी तकनीक को भी हथियार प्रतिबंध के दायरे में रखने की बात कही गई है। अमेरिकी प्रस्ताव में सभी देशों से सूडान के युद्धरत पक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सैन्य, वित्तीय और लॉजिस्टिक मदद बंद करने की मांग की गई है। अमेरिका का कहना है कि बाहरी सहायता युद्ध को जारी रखने और शांति प्रयासों को कमजोर करने में भूमिका निभा रही है।

## अमेरिका में एआई की वजह से नहीं जाएगी शिक्षकों की नौकरी: शिक्षा मंत्री बोलीं- मशीन नहीं ले सकता इंसान की जगह

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी शिक्षा मंत्री लिंडा मैकमोहन ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय और स्पष्ट सीमाएं तय होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ढ्ढ को कभी भी शिक्षकों के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मैकमोहन ने कहा कि ढ्ढ अब शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक चाहे जितनी विकसित हो जाए, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच मानवीय संवाद की जगह नहीं ले सकती।

**एआई को अपनाना जरूरी, लेकिन सुरक्षा उपाय भी हों :** मैकमोहन ने कहा कि सरकार ने फिलहाल एआई को रेगुलेट करने के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की है, लेकिन वह शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि ढ्ढ आ चुका है और स्कूलों को इससे दूरी बनाने के बजाय इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। उन्होंने ऑस्टिन, टेक्सास के अल्फा स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने वहां ढ्ढ को वास्तविक कक्षा में काम करते हुए देखा है। उनके मुताबिक, इस तकनीक को अपनाने के साथ कुछ नियम और सुरक्षा सीमाएं तय करना भी जरूरी है, ताकि इसका इस्तेमाल छात्रों के हित में हो।



**शिक्षक की जगह नहीं ले सकता एआई :** अमेरिकी शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि एआई का इस्तेमाल शिक्षक के विकल्प के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच प्रत्यक्ष मानवीय संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। मैकमोहन के मुताबिक, तकनीक बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन शिक्षा केवल जानकारी हासिल करने का नाम नहीं है। कक्षा में शिक्षक का मार्गदर्शन, संवाद और बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

**कमजोर छात्रों से लेकर तेज छात्रों तक :** मैकमोहन ने एआई के संभावित फायदों को गिनाते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए एक व्यक्तिगत ट्यूटर की तरह काम कर सकता है। जो छात्र किसी विषय में पीछे रह गए हैं, वे ढ्ढ की मदद से पाठ दोबारा समझ सकते हैं और अपनी गति से अभ्यास कर सकते हैं। वहीं, जो छात्र अपनी कक्षा के स्तर से आगे हैं, उनके लिए ढ्ढ ज्यादा उन्नत सामग्री और चुनौतीपूर्ण पाठ उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह छात्रों के लिए एक बेहद उपयोगी अवसर साबित हो सकती है।

**शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी :** मैकमोहन ने ट्रंप प्रशासन की शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की योजना पर भी बात की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि कई जिम्मेदारियां संघीय सरकार से वापस राज्यों को दी जाएं। मैकमोहन के मुताबिक, ट्रंप का मानना है कि दशकों तक भारी खर्च के बावजूद अमेरिकी छात्रों के परीक्षा परिणाम लगातार कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे कहा था कि देश अपने बच्चों के लिए अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाया है और अब इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है।

**3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च, फिर भी टेस्ट स्कोर में गिरावट :** मैकमोहन ने कहा कि अमेरिकी शिक्षा विभाग 1980 में अस्तित्व में आया और तब से शिक्षा पर 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद छात्रों के टेस्ट स्कोर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। उन्होंने इसी आधार पर तर्क दिया कि मौजूदा संघीय शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। उनका कहना है कि शिक्षा से जुड़ी ज्यादा जिम्मेदारियां राज्यों को सौंपने से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और स्कूलों की जरूरत के मुताबिक नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। मैकमोहन ने कहा कि शिक्षा विभाग को पूरी तरह खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी। इसलिए प्रशासन फिलहाल यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विभाग की कुछ जिम्मेदारियां दूसरी संघीय एजेंसियां ज्यादा प्रभावी ढंग से संभाल सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन विभिन्न विभागों के बीच अंतर-एजेंसी समझौते कर रहा है और कुछ कार्यक्रमों तथा जिम्मेदारियों को दूसरी एजेंसियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैकमोहन के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य कांग्रेस के सामने यह साबित करना है कि शिक्षा से जुड़े कुछ काम शिक्षा विभाग के बाहर भी प्रभावी तरीके से किए जा सकते हैं।

**राज्यों को ज्यादा अधिकार देने की तैयारी :** मैकमोहन ने कहा कि शिक्षा को राज्यों के स्तर पर वापस ले जाना ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उनका तर्क है कि स्थानीय और राज्य सरकारें अपने छात्रों की जरूरतों को संघीय सरकार की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को मुख्य रूप से कांग्रेस द्वारा स्वीकृत धनराशि को आगे पहुंचाने वाली संस्था के रूप में भी वर्णित किया। उनके मुताबिक, विभाग के कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो शिक्षा विभाग के गठन से पहले दूसरी संघीय एजेंसियों के माध्यम से संचालित होते थे।

## ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से राहत-पोस्टल बैलेट से मतदान संबंधी आदेश को मिली मंजूरी, मध्यावधि चुनाव पर क्या असर

**वाशिंगटन, एजेंसी।** सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डाक मतपत्र से मतदान को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उनका प्रशासन आगामी मध्यावधि चुनावों से पहले इसे कितना लागू कर पाएगा। इस निर्णय से अतिरिक्त अदालती चुनौतियों की संभावना बनी हुई है, जो ट्रंप के आदेश को और धीमा कर सकती हैं। अमेरिकी डाक विभाग ने पिछले सप्ताह आदेश को लागू करने की अपनी योजना बताई थी। दरअसल, कुछ राज्यों में कुछ ही हफ्तों में मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे बड़े बदलाव लागू करने के लिए समय कम है। ट्रंप लंबे समय से डाक मतपत्र मतदान को धोखाधड़ी का जरिया बताते रहे हैं, हालांकि इसके विपरीत मजबूत सबूत मौजूद हैं। उन्होंने स्वयं भी इस मतदान पद्धति का उपयोग किया है। न्याय विभाग ने उच्च न्यायालय से मध्यावधि चुनावों से पहले परिवर्तनों को लागू करने की अनुमति देने के लिए एक आपातकालीन अपील दायर की थी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर मार्च में हस्ताक्षर किए गए थे। यह उनके प्रशासन से योग्य मतदाताओं की सूची बनाने और अमेरिकी डाक विभाग को केवल उन सूचियों में शामिल लोगों को डाक मतपत्र वितरित करने का आदेश देता है।



**आदेश को चुनौती और अदालती निर्णय :** 23 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के डेमोक्रेटिक अधिकारियों ने इस आदेश को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान राज्यों और कांग्रेस को चुनाव कराने की शक्ति देता है। ट्रंप के बदलावों से अराजकता और पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग हो सकता है। राज्यों के वकीलों ने लिखा, इस गिरावट के चुनावों के इतने करीब ऐसे परिवर्तनकारी बदलावों को प्रभावी होने के परिणाम अत्यधिक होंगे।% मैसाचुसेट्स में एक न्यायाधीश ने उन राज्यों में मध्यावधि चुनावों के लिए योजना को रोक दिया था। एक अपील अदालत ने उनके फैसले को बरकरार रखा। बाद में उन्होंने इसे देशव्यापी रूप से रोकने का दूसरा आदेश दिया। ट्रंप प्रशासन ने जुलाई के अंत में प्रक्रियात्मक आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने तर्क दिया कि राज्यों ने बहुत जल्दी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने वाशिंगटन से आए एक अन्य फैसले का भी हवाला दिया, जहां एक न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।

## ईरान में युद्ध और महंगाई के बीच युवाओं का सुकून भी छिना, दर्जनों कैफे सील, क्या चाहती है हुकूमत

**लैली निकूनाजार/येगाने तोरबाती, तेहरान, एजेंसी।** युद्ध के साये, आसमान छूती महंगाई और रोजगार के घटते अवसरों के बीच ईरान की युवा पीढ़ी के पास सामान्य जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही सस्ता जरिया बचा था-शाम के वक्त दोस्तों के साथ किसी कॉफी शॉप में बैठकर थोड़ा वक्त सुकून से काटना। लेकिन फुटपाथ में कुर्सियों पर पसरे युवा, सिगरेट का धुआं, बेपरवाह गपशप और कभी-कभार छिपाकर बीयर पीने (जिसकी सजा देश में कोड़े हैं), वाले ये दृश्य कट्टरपंथी हुकूमत को खामोश बगावत नजर आने लगे। नतीजा, पुलिस-प्रशासन कैफे बंद कराने लगा।

राजधानी तेहरान समेत देश के कई शहरों में हाल में दर्जनों कैफे, रेस्टोरेंट और बुटीक सील किए?गए?हैं। वैसे तो वजह यही बताई गई कि अनिवार्य हिजाब कानून और इस्लामी मूल्यों की अनदेखी हो रही है। लेकिन तेहरान के कैफे मालिक आमिर का कहना है कि यह हुकूमत की बेचैनी और युद्ध से थके समाज को नियंत्रित करने की कोशिश है। आमिर कहते हैं, हम खुद को यही तसल्ली देते हैं कि यह सिर्फ एक लहर है। ईरान के कॉफी शॉप कल्चर पर किताब लिखने वाली हालेह मीर मीरी के अनुसार, इसमें युवा जिंदगी जीने के वैकल्पिक रास्ते तलाशते हैं। तेहरान की आर्टिस्ट मोना कहती हैं, कैफे छोटे होने से लोग फुटपाथ पर खड़े होकर बातें करने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि यह प्रदर्शन की तैयारी है। ईरान में कैफे के आसपास इस तरह युवाओं की भीड़ जुटने को सरकार संभावित प्रदर्शन से जोड़कर देख रही है। यही नहीं, सार्वजनिक जगह पर हावी होने की कोशिश में भी सरकार कड़े कदम उठा रही है। क्योंकि युद्ध की अनिश्चितता के बीच हुकूमत अपने समर्थन में रैलियां निकाल रही है। ऐसे माहौल में कैफे का यह आजाद माहौल सरकारी नैरेटिव को सीधी चुनौती देता है। ईरान में इन दिनों एक पुराना सामाजिक और सांस्कृतिक टकराव फिर से भड़क उठा है। ईरान की राजधानी तेहरान और ऐतिहासिक शहर शिराज की सड़कों पर आजकल एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है।

## ट्रंप का बड़ा खुलासा- दो हफ्ते में अमेरिका आएंगे शी जिनपिंग, व्हाइट हाउस में बन रहा 'चीन जैसा' ग्रेट हॉल

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को खुलासा किया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब दो हफ्ते में अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने यह घोषणा व्हाइट हाउस के पास निर्माणाधीन नए बॉलरूम और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हुए की। उन्होंने परियोजना की तुलना चीन के 'ग्रेट हॉल' से की और साथ ही नए हेलीपोर्ट को भी वर्षों से लंबित जरूरत बताया। हालांकि, शी की यात्रा को लेकर अभी चीन या व्हाइट हाउस की ओर से आधिकारिक कार्यक्रम और अन्य विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रंप ने यह जानकारी व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित 'बैक-टू-स्कूल' कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान दी। हालांकि, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ होने वाली बातचीत की तारीख, कार्यक्रम और यात्रा से जुड़ी अन्य



जानकारियां साझा नहीं कीं। ट्रंप ने कहा,राष्ट्रपति शी दो हफ्ते में आ रहे हैं। मैं दो महीने पहले चीन गया था और हमने चीन का 'ग्रेट हॉल' देखा था। अब अमेरिका में भी हमारा अपना 'ग्रेट हॉल' होगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है।÷

ट्रंप ने व्हाइट हाउस परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों से इस प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स को जोड़ते हुए बताया कि परियोजना में एक भव्य बॉलरूम के साथ-साथ एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी शामिल होगा। उन्होंने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, हम वहां एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स और एक बॉलरूम बना रहे हैं, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बेहतरीन होगा। शिक्षा पर अपनी बात रखने के बाद राष्ट्रपति एक बार फिर निर्माण कार्य की चर्चा पर लौट आए। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद छात्रों और उनके परिवारों को अपने साथ निर्माण स्थल देखने के लिए आमंत्रित किया। ट्रंप ने कहा, आप ठीक बगल में व्हाइट हाउस के पास बन रही शानदार इमारत देखेंगे। वही बॉलरूम और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स होगा। यह अद्भुत है। उन्होंने बताया कि प्रशासन व्हाइट हाउस में एक नया हेलीपोर्ट भी बना रहा है। ट्रंप के मुताबिक, पहले हेलीकॉप्टरों को घास पर उतरना पड़ता था, जिससे गीले मौसम में परेशानी और सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा होते थे। ट्रंप ने कहा, हम एक सुंदर हेलीपोर्ट बना रहे हैं, जिसकी मांग कई वर्षों से की जा रही थी। हेलीकॉप्टर को गीली घास पर उतरना पड़ता था, जो खराब और खतरनाक था।%रोज गार्डन में जुटे बच्चों को निर्माण कार्य दिखाने को लेकर ट्रंप खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने निर्माण स्थल से आने वाली आवाजों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें निर्माण कार्य की आवाज पसंद है। ट्रंप ने कहा, मुझे निर्माण कार्य की आवाज बहुत पसंद है। जब मैं बाहर वह शोर-शराबा सुनता हूं।

## चीन में भारतीय फैशन का जलवा, कुर्ते से साड़ी तक का बढ़ा क्रेज; क्यों पसंद आ रहा देसी अंदाज

**शंघाई/बीजिंग, एजेंसी।** पश्चिमी देशों और रूस में भारतीय एथनिक फैशन की पहचान बनने के बाद अब चीन जैसे पड़ोसी देश में भी भारतीय पहनावे का नया क्रेज देखा जा रहा है। बीजिंग से शंघाई तक चीनी युवा सलवार-कुर्ती और इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन आउटफिट्स पहनकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो महिलाओं को भी साड़ी में देखा जा रहा है। लोग पलिनन के लंबे-छोटे कुर्तो को डेनिम जींस, ट्राउजर और वाइट स्नीकर्स के साथ पेयर करके मिनिमलिस्टिक लुक अपना रहे हैं। चीन के उमस भरे मौसम में सांस लेने योग्य भारतीय कॉटन, खादी और चंदेरी फैब्रिक की भारी मांग है। श्याओहांगशू (रेड बुक) ट्रेंड्स डाटा के मुताबिक, शंघाई के प्रसिद्ध अंफु रोड और उहांग रोड जैसे स्ट्रीट-फैशन हब्स पर कुर्ता-डेनिम लुक छाया हुआ है। शैनक्सी



साउथ रोड के मल्टी-ब्रांड बुटीक में भी भारतीय फैब्रिक हावी है। वहीं, बीजिंग के सानलीतुन स्ट्रीट जोन और ताइगू ली एवेन्यू पर युवा कुर्तो को डेनिम व स्नीकर्स के साथ स्टाइल कर रहे हैं। चीनी अखबार चायना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, फैशन शो और बीटूबी मीट्स में लेबलहुड की संस्थापक ताशा लियू ने इस फ्यूजन ट्रेंड को बढ़ावा दिया, जिसके बाद ताओबाओ और श्याओहांगशू के सेलर नेटवर्क ने भारी मात्रा में बल्क ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं।

फैशन शो और बीटूबी मीट्स के दौरान चीनी रिटेलर्स ने भारतीय टेक्सटाइल और फ्यूजन वियर के लिए 12 लाख डॉलर (10 करोड़ रुपये) के शुरुआती सप्लाई ऑर्डर्स दिए हैं, जो बहुत बड़ी रकम है। 6 माह के दौरान चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स (ताओबाओ व टीमाल) पर इंडियन स्टाइल एथनिक कुर्ती और मसाला चाय मिक्स की बिक्री 45त्न तक बढ़ गई है।

चीन के मेट्रो शहरों (शंघाई, बीजिंग और चेंगदू) में इन दिनों भारतीय लाइफस्टाइल और एथनिक फैशन का एक अनोखा उभार देखने को मिल रहा है। चीन के सबसे बड़े लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म श्याओहांगशू पर भारतीय पहनावे, इंडो-फ्यूजन स्टाइलिंग और आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के ट्रेंड्स की बाढ़ आ गई है। खास तौर पर साड़ियों का भी चलन खूब देखने को मिल रहा है।

रेड कार्पेट और फैशन शो में लंबी कतारें = शंघाई के अंतरराष्ट्रीय फैशन कॉरिडोर में ईस्ट-मीट्स-वेस्ट फ्यूजन शो और बीजिंग कल्चरल एक्सपो हुआ, जिसमें भारतीय एथनिक व इंडो-वेस्टर्न डिजाइनों का प्रदर्शन हुआ। चीनी फैशन इन्फ्लुएंसर ली जियाओयान शंघाई की प्रसिद्ध स्टाइलिस्ट चेन वेई ने भारतीय चंदेरी, बनारसी और ब्लॉक-प्रिंट सिल्क के साथ आधुनिक कट-आउट्स का प्रयोग कर रेड कार्पेट पर धूम मचाई। इस 3 दिनी शो में 15,000 से अधिक दर्शक व खरीदार मौजूद रहे।

## खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो पर सख्ती; टिकटॉक समेत इन प्लेटफॉर्म को सरकार की चेतावनी, क्या कहा

**लंदन, एजेंसी।** ब्रिटेन की सरकार ने सोमवार को टिकटॉक और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों से कहा कि वे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने वाले वीडियो हटाएं। सरकार ने इन वीडियो को वायरल होने से रोकने को कहा है। यह कदम एक सड़क हादसे में दो पुलिस अधिकारियों और पांच युवकों की मौत के बाद उठाया गया है। हादसे के समय एक कार सड़क की गलत दिशा में जा रही थी। शनिवार को अधिकारी मैथ्यू ब्लेड्स और टॉम क्लॉ की मौत हो गई। उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड में एक वोक्सवैगन कार सड़क पर गलत दिशा में जा रही थी। इसी दौरान वह पुलिस अधिकारियों की गाड़ी से टकरा गई। कार में सवार पांच लोगों की भी मौके पर मौत हो गई। इनमें तीन लड़के थे। उनकी उम्र 17 और 18 साल थी। दो अन्य पुरुष थे। दोनों की उम्र 23 साल थी।

**खतरनाक ड्राइविंग के वीडियो क्यों चिंता बढ़ा रहे हैं :** यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब सोशल मीडिया में उन वायरल वीडियो को लेकर चिंता बढ़ी है, जिनमें लोग खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते दिख रहे हैं। ऐसे वीडियो खुद गाड़ी चलाने वाले लोग पोस्ट करते हैं। कई बार गाड़ी में बैठे दूसरे लोग भी इन्हें सोशल मीडिया पर डालते हैं। ब्रिटिश मीडिया की खबरों के मुताबिक, शनिवार को वोक्सवैगन कार में मारे गए लोगों में से एक ने पहले भी ऐसा वीडियो पोस्ट किया था। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ल्यूक पोलार्ड ने कहा कि सरकार ने टिकटॉक और ऐसी दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों से ऐसे खराब कंटेंट को हटाने और अपनी कार्रवाई तेज करने को कहा है। उन्होंने बीबीसी से कहा, हमने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात की है, जहां सड़कों पर इस तरह के खतरनाक व्यवहार का जश्न मनाने वाला कंटेंट डाला जा रहा है। हमने उनसे ऐसा कंटेंट हटाने को कहा है।

पोलार्ड ने आगे कहा, इन कंपनियों ने कुछ नियमों का विरोध करते हुए कहा था कि वे खुद अपने प्लेटफॉर्म की निगरानी कर सकती हैं। अब यह दिखाने का सही मौका है कि वे ऐसा कर सकती हैं। सड़कों पर खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा देने वाला कंटेंट हटाया जाए।

प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के कार्यालय ने कहा कि वीडियो और मनोरंजन के लिए खतरनाक ड्राइविंग को बढ़ावा देना बेहद शर्मनाक है। कार्यालय ने कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ब्रिटेन के मीडिया नियामक को सरकार का पूरा समर्थन है। टिकटॉक ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, कंपनी ने कहा कि उसकी नीतियों के तहत ऐसे कंटेंट पर सख्त रोक है, जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकता है। पुलिस ने बताया कि जिस कार से यह जानलेवा हादसा हुआ, उस पर नकली नंबर प्लेट लगी थी। इसका इस्तेमाल पुलिस से बचने के लिए किया गया था। पुलिस ने कहा कि हादसे से पहले संदिग्ध आपराधिक गतिविधियों के मामले में सोमवार को 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें हथियार रखने का मामला भी शामिल है। एक अलग मामले में, आयरलैंड के काउंटी किल्डेयर में पिछले हफ्ते चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। उनकी कार को राजमार्ग पर गलत दिशा में जा रही दूसरी कार ने टक्कर मार दी।

## हेगसेथ बोले- जरूरत पड़ी तो ईरान पर मिसाइल से हमला; सख्ती पर इस्राइली पीएम नेतन्याहू क्या बोले

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक और सैन्य दबाव को एक साथ तेज कर दिया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने होर्मुज जलडमरूमध्य समेत ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा है, जबकि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के जरिए ईरान के तेल, वित्तीय नेटवर्क और प्रतिबंधों से बचने वाले तंत्र को निशाना बनाने की घोषणा की है। दूसरी ओर, ईरान ने संकट से निपटने का भरोसा जताया है और इस्राइल ने अमेरिकी कदमों का समर्थन किया है। इससे तेहरान पर आर्थिक दबाव के साथ संभावित सैन्य टकराव का जोखिम भी बढ़ गया है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति साफ तौर पर दो मोर्चों पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है एक तरफ आर्थिक घेराबंदी और दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई का खुला विकल्प।

**होर्मुज में भी सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं :** विस्कॉन्सिन के ओशकोश दौरे के दौरान हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना को बिल्कुल खत्म नहीं कर रहा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या फिलहाल सैन्य हमलों का विकल्प रोक दिया गया है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसा नहीं है। हेगसेथ के मुताबिक, अगर ईरान अमेरिकी सेना से टकराता है या ऐसी कार्रवाई करता है जिसे वॉशिंगटन सीमा पार करना मानता है, तो अमेरिका जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल आर्थिक दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर होर्मुज जलडमरूमध्य या ईरान के आसपास किसी भी इलाके में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है।

**अमेरिका का दावा-होर्मुज पर मजबूत पकड़ :** हेगसेथ ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और वहां से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करने की क्षमता रखती है। उनके अनुसार, ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार दबाव में है और तेहरान यह भी समझता है कि जलडमरूमध्य में



अमेरिकी सैन्य क्षमता उसके मुकाबले काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इस क्षेत्र से व्यापार और तेल की आवाजाही को प्रभावित करने की कुछ क्षमता जरूर है, लेकिन अमेरिका के पास समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने की बेहतर क्षमता मौजूद है। उनका दावा है कि इसी वजह से तेल का प्रवाह जारी रखा जा सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान के दबाव को सीमित किया जा सकता है।

**ईरानी नौसेना और मिसाइल क्षमता को नुकसान का दावा :** हेगसेथ ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई से ईरान की नौसेना, रडार और मिसाइल प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि ईरान के पास अब भी कुछ सैन्य क्षमताएं मौजूद हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री के मुताबिक, ईरान की मौजूदा सैन्य क्षमता पहले जैसी नहीं रह गई है। इसी आधार पर वॉशिंगटन का मानना है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है और तेल की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति को जारी रख सकता है।

**आर्थिक दबाव के साथ परमाणु वार्ता का लक्ष्य :** हेगसेथ ने कहा कि लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिकी रणनीति का मकसद तेहरान की आर्थिक क्षमता को इतना कमजोर करना है कि उसके सामने बातचीत के अलावा विकल्प सीमित रह जाएं। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव और सैन्य विकल्प दोनों एक-दूसरे के समानांतर चल रहे हैं। वॉशिंगटन फिलहाल आर्थिक हथियार को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना खुली रखी गई है।

**ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट से ईरान की वित्तीय घेराबंदी :** अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने की घोषणा की। उनके मुताबिक, इस अभियान का लक्ष्य दुनियाभर में ईरान के वित्तीय संपर्कों को तोड़ना और उन सभी आय स्रोतों पर कार्रवाई करना है जो ईरानी सरकार तथा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। अमेरिका ने इस अभियान के तहत करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है। इनमें ईरान की सैन्य गतिविधियों, खरीद नेटवर्क और पेट्रोलियम तथा पेट्रोकेमिकल कारोबार से कथित रूप से जुड़े लोग और संस्थाएं शामिल हैं।

# कारुआना ने ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जीत हासिल की

## पहले क्लासिकल गेम के बाद 6-0 की बढ़त

**नईदिल्ली, एजेंसी।** सेंट लुइस में खेले जा रहे ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026 के खिताबी मुकाबले में ग्रैंडमास्टर फैबियानो कारुआना ने भारत के आर प्रज्ञानानंदा को हरा दिया। कारुआना ने फाइनल के पहले क्लासिकल गेम में प्रज्ञानानंदा को शिकस्त दी। इस जीत से अमेरिका के कारुआना ने मैच में 6-0 की बढ़त बना ली। मुकाबले में प्रज्ञानानंदा लंबे समय तक बराबरी पर थे, लेकिन 28वीं चाल में हुई गलती के बाद कारुआना ने गेम अपने नाम कर लिया। वहीं तीसरे स्थान के मुकाबले में विंसेंट कीमर और वेस्ली सो का पहला क्लासिकल गेम ड्रॉ रहा और दोनों का स्कोर 3-3 है।

# बायर्न म्यूनिख ने ड्रिसेन और एबरल का अनुबंध जून 2029 तक बढ़ाया

**बर्लिन, एजेंसी ।** बायर्न म्यूनिख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जान-क्रिश्चियन ड्रिसेन और स्पोर्टिंग बोर्ड मेंबर मैक्स एबरल का अनुबंध जून 2029 तक बढ़ा दिया है। शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले को बायर्न के सुपरवाइजरी बोर्ड ने मंगलवार को एक बैठक में मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद ड्रिसेन और एबरल का 2027 में समाप्त होने वाला कार्यकाल 2 साल बढ़ गया। ड्रिसेन 2013 में

मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर बायर्न में शामिल हुए थे और एक साल बाद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। वह मई 2023 से सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। अनुबंध बढ़ाए जाने के बाद ड्रिसेन ने कहा, 'मैं सुपरवाइजरी बोर्ड को उनके भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहते हैं कि एफसी बायर्न शीर्ष क्लब बना रहे जिस पर हम सभी को गर्व है। यही हमें प्रेरित करता है। हमने अभी भी बहुत योजनाएं बनाई हैं। ' 52 साल के एबरल, बोरूसिया मोनचेंग्लाडबैक और आरबी लीपजिग में प्रबंधन में काम करने के बाद मार्च 2024 में स्पोर्टिंग बोर्ड मेंबर के तौर पर बायर्न लौटे। वह छह साल की उम्र में बायर्न में शामिल हुए, यूथ सिस्टम में आगे बढ़े और बाद में क्लब के लिए अपना पेशेवर डेब्यू किया। एबरल ने कहा, 'जब से मैं यूथ टीमों में था, तब से एफसी बायर्न मेरे दिल के करीब रहा है। सुपरवाइजरी बोर्ड का भरोसा एक कीमती निशानी है और मैं इससे बहुत खुश हूं। ' सुपरवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हर्बर्ट हैनर ने कहा कि स्थिरता जरूरी है, स्थिरता ताकत देती है। हमें क्लब को सबसे ऊंचे स्तर पर लगातार विकसित करने के लिए हमें दोनों की जरूरत है। बायर्न यूरोप के शीर्ष क्लबों में अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। हैनर ने कहा, ड्रेसेन, एबरल और मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव रूवेन कैस्पर का मैनेजमेंट बोर्ड क्लब को पिच पर और पिच के बाहर आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में था। जुलाई 2024 से बायर्न के मैनेजमेंट बोर्ड में तीन सदस्य हैं। इस स्ट्रक्चर का मकसद समन्वय बनाते हुए जल्दी फैसले लेने में मदद करना है।

**विमेंस एशिया कप**

# पहली बार खेल रही इंडोनेशिया ने किया टीम का ऐलान

**नई दिल्ली, एजेंसी।** महिला एशिया कप 2026 का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में होना है। इंडोनेशिया की महिला टीम ने पहली बार टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले इंडोनेशिया ने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान करने वाली इंडोनेशिया आखिरी टीम है। टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। अनुभवी कप्तान नंदा सकारिनी टीम का नेतृत्व करेंगी, जबकि वेलिक के साथ मिलकर बेहतरीन बॉलिंग ग्रुप में शामिल होंगी। टीम में आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की स्टार खिलाड़ी वेसिका रत्ना देवी, पुत्री सुवानदेवी और सांग मेयरपिरानी शामिल हैं। देसी वुलंडारी, ली कियाओ और नी काडेक एरियानी भी टीम का हिस्सा हैं। इंडोनेशियाई टीम का क्वालीफिकेशन कैंपेन बहुत अच्छा रहा, वे थाईलैंड से हारने से पहले सेमीफाइनल तक पहुंचीं, और तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में हांगकांग, चीन से हार गईं। टीम ने जून में एसीसी विमेंस प्रीमियर कप के जरिए क्वालीफाई किया था। पूरे इवेंट में टीम के लिए सिर्फ 11 सदस्य खेले थे। सकारिनी क्वालीफाइंग में टीम की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थीं। इंडोनेशिया एशिया कप में ग्रुप बी का हिस्सा है। इस ग्रुप की अन्य तीन टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई हैं। एशिया कप कैंपेन में इंडोनेशिया का पहला मैच 31 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ है, इसके बाद वे 2 सितंबर को श्रीलंका और 4 सितंबर को यूएई का सामना करेंगे। पहली हार टूर्नामेंट में उतरी इंडोनेशिया के प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस की नजर रहेगी। महिला एशिया कप के लिए इंडोनेशिया की टीमः नंदा सकारिनी (कप्तान), काडेक विंडा प्रास्तिनी, रहमावती पंगेस्टुटी, वेसिका रत्ना देवी, राडा रानी, ??देसी वुलंडारी, पुत्री सुवांडेवी, किसी सलीसा कासे, सांग मेप्रियानी, नी काडेक एरियानी, डेनीं बांगी, दारा अगुंग लक्ष्मी, ली कियाओ, मारिया कोराजोन वोम्बाकी, सोफिया वेलिक।

# एंटीगुआ ने बारबाडोस ट्राइडेंट्स को 30 रन से हराया, जोसुआ जेम्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच

**एंटीगुआ, एजेंसी।** कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 का 16वां मुकाबला सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्सल और बारबाडोस ट्राइडेंट्स के बीच खेला गया। एंटीगुआ ने बारबुडा को 30 रन से हरा दिया। बारबाडोस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एंटीगुआ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 155 रन बनाए। टीम के लिए सबसे ज्यादा 56 रन कप्तान मोईन अली ने बनाए। 37 गेंदों पर खेली गई इस नाबाद पारी में मोईन ने 4 छक्के और 3 चौके लगाए। इसके अलावा, करिमा गोरे ने 27 और आमिर जंगू ने 26 रन बनाए। शमार स्प्रिंगर ने नाबाद 19 रन बनाए। बारबाडोस की तरफ से मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए।

# ब्राजील के खिलाफ मैच से पहले विश्वकप खेलने वाली इस टीम से होगा भारत का सामना

**नई दिल्ली, एजेंसी।** ब्राजील के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को 2026 फीफा विश्व कप में खेल चुकी पनामा से भिड़ेगी। पनामा फीफा रैंकिंग में 44वें स्थान पर है। यह मुकाबला खालिद जमील की टीम के लिए बड़ी चुनौती होने के साथ ब्राजील और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी मुकाबलों की तैयारी का अहम मौका होगा। भारतीय फुटबॉल टीम को ब्राजील के खिलाफ बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले एक और बड़ी चुनौती मिल गई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने मंगलवार को बताया कि भारत 26 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में पनामा की मेजबानी करेगा।

हालांकि, मैच किस मैदान पर खेला जाएगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पनामा 2026 फीफा विश्व कप में हिस्सा ले चुका है। ऐसे में ब्राजील से भिड़ने से ठीक पहले भारतीय टीम को एक और विश्व कप टीम के खिलाफ खुद को परखने का मौका मिलेगा।

**फीफा रैंकिंग में 44वें नंबर पर है पनामा** – पनामा इस समय फीफा की ताजा रैंकिंग में 44वें स्थान पर है। यानी वह दुनिया की शीर्ष-50 टीमों में शामिल है। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला इसलिए भी अहम होगा क्योंकि खालिद जमील की टीम को मजबूत अंतरराष्ट्रीय विपक्ष के खिलाफ अपनी तैयारी और स्तर को परखने का मौका मिलेगा।

### विश्व कप टीमों के खिलाफ लगातार मुकाबले

पनामा के खिलाफ मुकाबला भारत के लिए विश्व कप में खेलने वाली टीमों के खिलाफ प्रस्तावित चार मैचों की शुरुआत करेगा। इसके बाद भारतीय टीम 3 अक्टूबर को ब्राजील से भिड़ेगी। नवंबर में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दो मुकाबले खेलने हैं। दोनों टीमें 12 और 15 नवंबर को आमने-सामने होंगी। इस तरह भारतीय टीम को इस अवधि में उन टीमों के खिलाफ खेलने का शानदार मौका मिलेगा, जो 2026 विश्व कप का हिस्सा रही हैं।

# बीबीएल में ड्राफ्ट सिस्टम खत्म, अब खिलाड़ियों को होगा और फायदा

**सिडनी, एजेंसी।** बिग बैश लीग (बीबीएल) अनुबंध से जुड़ी रोक गुरुवार से हटने के बाद इस टूर्नामेंट में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई और विदेशी खिलाड़ियों को अधिक राशि मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ महीनों की बातचीत और क्लबों से मिले फीडबैक के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार डब्ल्यूबीबीएल सीजन शुरू होने से छह सप्ताह पहले अनुबंध से जुड़े नए नियम घोषित कर दिए। नए नियमों के तहत विदेशी खिलाड़ियों के लिए ड्राफ्टा व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है और बड़े घरेलू खिलाड़ियों को ज्यादा पैसे देने के मकसद से जरूरी बड़े घरेलू खिलाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। क्लबों को विदेशी खिलाड़ियों को साइन न करने का विकल्प भी दिया गया है। यह रोक गुरुवार सुबह नौ बजे हट जाएगी और इससे बेन स्टोक्स और फिन एलन जैसे खिलाड़ियों के लिए बीबीएल क्लबों के साथ सीधे रिकॉर्ड अनुबंध साइन करने का रास्ता खुल जाएगा। साथ ही मेलबर्न रेनेगेड्स छोड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया के लेग-स्पिनर एडम जम्पा को भी आखिरकार कोई क्लब मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के टी-20 विकेटकीपर जॉश इंग्लिश को भी सैद्धांतिक रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया है, हालांकि, टेस्ट ड्यूटी की वजह से हो सकता है कि वह आने वाले बीबीएल के किसी भी हिस्से के लिए उपलब्ध न हों, जिससे आने वाले सीजन के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने की उनकी संभावना बेहद कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बीबीएल खिलाड़ी और कई क्लब लंबे समय से विदेशी खिलाड़ियों के लिए बने 'ड्राफ्ट' सिस्टम से परेशान थे। इस सिस्टम की वजह से कई बार कम मशहूर विदेशी खिलाड़ियों को ड्राफ्ट के नियमों के कारण सबसे अच्छे लोकल खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा पैसे मिल जाते थे। डब्ल्यूबीबीएल में भी यही नियम लागू होंगे। विदेशी खिलाड़ियों के लिए कोई न्यूनतम संख्या तय नहीं होगी, 15 खिलाड़ियों की टीम में तीन 'मार्की' खिलाड़ी होंगे जिनका वेतन अधिक होगा। बीबीएल के बॉस एलिस्टर डॉब्सन ने बताया, 'खिलाड़ियों का बाजार लगातार बदल रहा है और बीबीएल और डब्ल्यूबीबीएल जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। क्लबों के पास अलग-अलग खिलाड़ियों की वैल्यू और उनके घरेलू या विदेशी होने के आधार पर अपना आकलन करने की आजादी होना जरूरी है, और आखिरकार बात यही है कि क्लबों को अपनी टीम को लेकर आजादी मिले। इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि हमारी लीग में बेहतरीन विदेशी खिलाड़ी आएंगे क्योंकि वे हर टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे।

# न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है: रोजर फेडरर

**न्यूयॉर्क, एजेंसी।** दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का आर्थर ऐश स्टेडियम में एक यादगार एग्जिबिशन नाइट के दौरान हीरो जैसा स्वागत किया गया। दुनिया के सबसे बड़े टेनिस स्टेडियम में घुसते ही तालियों से स्वागत किया गया। इस अवसर पर 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने कहा कि न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फेडरर ने कहा, 'न्यूयॉर्क वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह अविश्वसनीय है। मेरे पास इस कोर्ट, यहां के फैंस, शहर की अविश्वसनीय यादें हैं। 2004, 2005 में – यहीं से सब कुछ शुरू हुआ, यहां की जीतों के साथ न्यूयॉर्क के लिए मेरा प्यार। ' फेडरर ने कहा, 'मुझे पहले दिन से ही इस शहर और इस कोर्ट से प्यार हो गया था। ' पूर्व खिलाड़ी ने 2004-2008 तक लगातार पांच यूएस ओपन जीते और टूर्नामेंट और शहर के साथ अपने खास कनेक्शन के बारे में बात की।

स्विस खिलाड़ी ने आर्थर ऐश स्टेडियम के सेंटर कोर्ट पर अपनी पहली मौजूदगी को याद किया, जो 2001 में अगासी के खिलाफ थी। फेडरर वह मुकाबला सीधे सेटों में हार गए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि सेंटर कोर्ट पर मेरा पहला मुकाबला आंद्रे के खिलाफ 2001 में था। उन्होंने मुझे 6-1, 6-2, 6-4 से हराया। मेरे पास कोई शॉट नहीं था। मैं ऐसा था, 'ठीक है, इतना आसान नहीं है, इतना तेज नहीं है, रोजर'। स्टेडियम के वीडियो बोर्ड पर एक्टर मैथ्यू मैककोनाघी का नैरेट किया हुआ एक हाइप वीडियो दिखाया गया, और फैशन आइकन एना विंटोर ने रॉडिक के खिलाफ फेडरर के एकल मैच से पहले सिक्का उछाला। सेरेना विलियम्स, फेलिक्स ऑगर-अलियासिमे, कैस्पर रूड और एलेक्जेंड्रा एला समेत कई मौजूदा और पुराने टेनिस स्टार भी मौजूद थे। फेडरर की यूएस ओपन में वापसी उनके पोस्ट-प्लेइंग करियर में एक और बड़ी उपलब्धि से कुछ दिन पहले हुई है। इस महीने की शुरुआत में अपना 45वां जन्मदिन मनाने वाले स्विस खिलाड़ी को शनिवार, 29 अगस्त को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। आंद्रे अगासी ने कहा, 'यह कितना कूल है कि यह बंदा इस साल हॉल ऑफ फेम में जा रहा है? बहुत बढ़िया, रोजर। मैं बहुत उत्साहित हूं। मुझे कहना होगा – मुझे लगता है कि मैं पहला इंसान था जिसे पता चला कि वह हॉल ऑफ फेम में जाने वाला है। जब उसने अपना 19वां स्लैम जीता, तो मुझे लगा, 'हां, वह कर सकता है'। उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि 20वां गैर-जरूरी (हंसते हुए) था। फिर भी, मैं सच में बहुत उत्साहित हूं क्योंकि इससे बाकी सभी लोग जो मुश्किल से अंदर जाने का तरीका ढूंढ पाए हैं, अपने बारे में बहुत बेहतर महसूस करते हैं। रॉडिक ने भी फेडरर के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए कहा, 'हमने बहुत खेला और उसने मुझे बहुत हराया। लेकिन हम हमेशा अपने करियर के बीच में दोस्ती बनाए रखने में कामयाब रहे और यह अब तक चली है और उम्मीद है कि हमेशा रहेगी। फेडरर ने 2022 में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया था। आखिरी बार फेडरर ने 2019 में यूएस ओपन खेला था।

# कोलंबो टेस्ट में छा गए सोनल दिनूषा, जड़ा ऐतिहासिक शतक

## बनाया सनत जयसूर्या- महेला जयवर्धने वाला महारिकॉर्ड

## श्रीलंका बनाम भारत

**कोलंबो, एजेंसी।** भारत के खिलाफ श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनूषा का शानदार प्रदर्शन जारी है. 25 साल के दिनूषा ने कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. दिनूषा ने इस मुकाबले में 103 रनों की पारी खेली. उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका ने 290 रनों का स्कोर बनाया, हालांकि दिनूषा अपनी टीम को फॉलोऑन से नहीं बचा सके, जिसके लिए श्रीलंका को 304 रनों का स्कोर बनाना था. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 503-9 रन बनाकर घोषित की. कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में सोनल दिनूषा ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. चौथे दिन यानी बुधवार (26 अगस्त) को दिनूषा ने 147 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यह इस सीरीज में दिनूषा का दूसरा शतक है. इससे पहले गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने एक पारी में 100 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 84 रन जड़े थे. अब कोलंबो में शतक के साथ उनका मौजूदा सीरीज में स्कोर 100, 84 और 103 हो गया है.

**जयसूर्या और जयवर्द्धने वाले क्लब में एंट्री** – सोनल दिनूषा अब भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाजों की खास सूची में शामिल हो गए हैं. इस सूची में सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्द्धने जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं. 25 साल के सोनल भारतीय ऑफ स्पनिर सारांश जैन की गेंद पर आउट हुए, उनको केएल राहुल ने आउट किया.

### भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज

- अरविंद डी सिल्वा – 3 बार
- कुमार संगकारा – 3 बार
- सनथ जयसूर्या – 2 बार
- महेला जयवर्धने – 2 बार
- थरंगा परानाविताना – 2 बार
- एंजेलो मैथ्यूज – 2 बार
- सोनल दिनूषा – 2 बार

### प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पूरा किया शतक दिनूषा

दिनूषा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गें द पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. गें द छोटी और ऑ फ स्टंप के बाहर थी, जिस पर उन्हों ने शानदार पुल शॉट खेला. गें द हवा में जरूर गई , ले किन आसानी से इनफील्ड को पार करते हु ए बाउं ड्री के बाहर पहुंच गई . शतक पू रा होने के बाद दिनू षा ने बल्ले को चू मा, हेलमेट उतारा और दर्श कों का अभिवादन स्वीकार किया. खास बात यह रही कि इस सीरीज में उनकी यह एक और लगभग बे दाग पारी रही. दोनों टीमों में दे वदा पडिकल ने उनसे ज्यादा रन बनाए हैं , ले किन दिनू षा की बल्ले बाजी पर नियं त्रण ने उन्हें इस सीरीज के सबसे प्रभावशाली बल्ले बाजों में शामिल कर दिया है .

### भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में कई शतक

- 2 – एवर्टन वीक्स (वेस्टइंडीज, 1948)
- 2 – गारफील्ड सोबर्स (वेस्टइंडीज, 1958)
- 2 – ज़हीर अब्बास (पाकिस्तान, 1978)
- 2 – दुलीप मेंडिस (श्रीलंका, 1982)
- 2 – रॉबिन स्मिथ (इंग्लैंड, 1990)
- 2 – गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका, 1996)
- 2 – जेसी राइडर (न्यूजीलैंड, 2009)
- 2 – सोनल दिनुषा (श्रीलंका, 2026)

### श्रीलंका फॉलोऑन के बाद भारत से 16 रन आगे, स्कोर-229/6:पसिंदु ने 92 रन बनाए; सुथार को दो विकेट, बारिश से मैच बाधित

भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में फॉलोऑन खेल रही श्रीलंका ने दूसरी पारी में 229/6 रन बनाए हैं। टीम ने भारत की पहली पारी के स्कोर से 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। सोनल दिनूषा 7 और केशरा नुवनथा 3 रन पर नाबाद हैं। चौथे दिन बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। पसिंदु सोरियाबंडारा 92 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मानव सुथार ने पवेलियन भेजा। सुथार ने कप्तान धनंजय डी सिल्वा को भी 23 रन पर आउट किया। इससे पहले निरोशन डिकवेला 6 रन पर सारांश जैन, कमिंदु मेंडिस 55 रन पर प्रसिद्ध कृष्णा, कमिल मिशारा 32 रन पर रवींद्र जडेजा और लाहिरू उदारा 3 रन पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर आउट हुए।

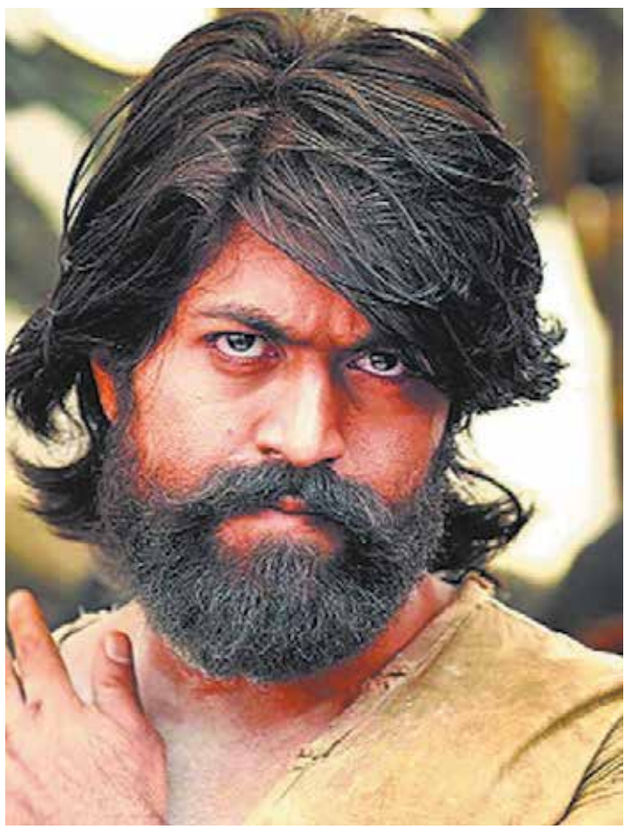

# 'धुरंधर 2' के साथ क्लैश पर यश का बड़ा बयान

# 'टॉक्सिक' के पोस्टपोन पर भी बोले एक्टर

**साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी फिल्म 'टॉक्सिक ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ क्लैश की बात सामने आई थी। अब यश ने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है।**

### फिल्म हुई बार-बार पोस्टपोन

फिल्म 'टॉक्सिक' पहले 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में बनी अनिश्चितता के चलते इसकी रिलीज 4 जून कर दी गई। इसके बाद फिल्म की रिलीज फिर टाल दी गई। अब हाल ही में इंडिया टीवी के शो 'आप की अदालत' में यश ने फिल्म की रिलीज टालने और बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर खुलकर बात की।

### 100-200 करोड़ खोने का डर नहीं

यश ने साफ कहा कि फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाने का फैसला इस डर से नहीं लिया गया कि बॉक्स ऑफिस पर 100 या 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो जाएगा। उनके लिए यह फैसला पैसे या अहंकार का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था। यश ने कहा कि अगर वह सिर्फ अपनी इमेज बचाने या किसी को कुछ साबित करने के लिए फिल्म को उसी तारीख पर रिलीज करते, तो वह असली अहंकार होता। उनके लिए सबसे जरूरी यह था कि वह दर्शकों से किया हुआ अपना वादा पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। एक्टर ने कहा कि उनका सबसे बड़ा डर फिल्म को लेकर था। अगर उन्हें लगता है कि वह दर्शकों को वह फिल्म नहीं दे पा रहे हैं, जिसका उन्होंने वादा किया था, तो वह पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना पसंद करेंगे।

### कभी जानबूझकर किसी फिल्म से क्लैश नहीं किया

बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर यश ने यह भी साफ किया कि उन्होंने कभी जानबूझकर किसी दूसरी फिल्म के साथ अपनी फिल्म का क्लैश नहीं किया। उन्होंने कहा, 'जो भी क्लैश आप बोल रहे हैं, उसमें मैं सीधे जाकर कभी क्लैश में नहीं आया। मेरी डेट पहले अनाउंस होती है और उसके बाद अगर कोई फिल्म आती है, तो वो क्लैश हो जाता है।' यश ने यह भी कहा कि उन्हें जिंदगी में कुछ खोने का डर नहीं है। उन्होंने कहा, जिंदगी में मुझे खोने का कुछ है ही नहीं, तो मुझे डर है ही नहीं।'

बॉक्स ऑफिस पर 100 या 200 करोड़ रुपये के नुकसान की बात पर भी यश ने इसे ज्यादा बड़ी चिंता नहीं माना। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल शून्य से की थी। आज उनके पास जो कुछ भी है, वह उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है। फिल्म 'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं। उनके अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां भी इसमें नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

# टॉक्सिक के किरदार नादिया को कियारा ने बताया मुश्किल

यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' में कियारा आडवाणी ने नादिया का किरदार निभाया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने एक अभिनेत्री के तौर पर अपने किरदार से जुड़े अनुभव साझा किए हैं।

कियारा के लिए फिल्म 'टॉक्सिक' उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म में नादिया का किरदार निभाने और उसकी मांग पर कियारा ने काफी कुछ लगा। एक्ट्रेस ने लिखा फिल्में हमें उस दुनिया में ले जाने का एक खूबसूरत तरीका होती हैं जिनमें हम असलियत में नहीं जा सकते। हर नया किरदार, हर नया सेट, हर चुनौती आपको कुछ ऐसा सिखाती है। आपकी क्षमताओं के बारे में बताती है। इस किरदार ने मुझे अपरिचित और मुश्किल चीजों के साथ भी सहज होना सिखाया। नया किरदार आपको नए कौशल, नए रोमांच और उस जुनून के लिए जो आपको बार-बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मेरे लिए ग्रोथ का मतलब हमेशा उस काम के लिए हामी भरना है जिसे करने से आपको थोड़ा डर लगे। यह किरदार नई स्किल्स, नए एडवेंचर्स और उस जुनून के नाम, जो आपको बार-बार नई चीजों में डूबने के लिए तैयार रखता है।

### फिल्म 'टॉक्सिक' के वक्त प्रेगनेंट थीं कियारा

फिल्म से जुड़े एक इवेंट में अभिनेता यश ने कियारा की खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा, 'मेरा यह सोचना है कि कियारा एक बेहद पेशेवर अभिनेत्री हैं। जब वह इस फिल्म के लिए कास्ट हुई थीं तो मैं काफी चिंतित था, क्योंकि यह फिल्म काफी चुनौतीपूर्ण है पर कियारा ने जिस तरह फिल्म के लिए खुद को समर्पित किया है। वह देखना बेहद शानदार रहा।

### कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'

फिल्म 'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं। उनके अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां भी इसमें नजर आएंगी। यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे ग्लोबली कई भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है।

## पुलकित सम्राट को पहचानना हुआ मुश्किल इस वजह से घटा ढाई किलो वजन

पुलकित सम्राट ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पुलकित इतने बदले हुए नजर आए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। इस स्टोरी के जरिए पुलकित ने फैंस को बताया कि वो इ दिनों बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। जानिए पुलकित ने और क्या कहा?

### स्टोरी में क्या बोले पुलकित

एक्टर ने बताया कि वो बीते कुछ दिनों से मलेरिया से पीड़ित हैं। अभिनेता ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनका वजन कम हो गया है। पुलकित ने तस्वीर शेयर कर जानकारी दी कि बीते कुछ दिनों में उनका ढाई किलो वजन कम हो गया। हालांकि, अभिनेता ने पॉजिटिविटी पर बात करते हुए कहा कि वह अपना वजन फिर से बैलेंस कर लेंगे। इसके साथ ही पुलकित ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें वह बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले इंटरव्यू में पुलकित ने सलमान खान को लेकर जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अपनी पहली फिल्म की रिलीज के वक्त हर नए कलाकार की तरह वह भी घबराए हुए थे, लेकिन तब सलमान खान की बातों ने स्टारडम के प्रति उनका नजरिया बदल दिया था।

### पुलकित का वर्कफ्रंट

पुलकित को आखिरी बार नेटफ्लिक्स सीरीज 'ग्लोरी' में देखा गया था। करण अंशुमन और कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बनी इस स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में दिव्येंदु और सुविंदर विक्की भी अहम भूमिकाओं में थे। सीरीज को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही अच्छे रिव्यू मिले। दूसरी तरफ उनकी आखिरी फिल्म 'राहु -केतु' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

## रोमांच बढ़ाएगी 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग', हत्या की गुत्थी सुलझाती दिखेंगी निमिषा सजयन

सोमवार को अभिनेता बरुन सोबती की अगली फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' की रिलीज डेट मेकर्स ने जारी की। यह एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा पर आधारित है। फिल्म एक हत्या के केस और उसकी तहकीकात से जुड़ी है। इसे 'पाताल लोक' के मेकर्स ने ही बनाया है।

### क्या है 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' की कहानी?

फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' में मुख्य किरदार बबीता सिंह नाम की एक एसआई का है, जिसके पास एक हत्या का केस आता है। इस दौरान उसका सामना कई रहस्यों और खतरों से होता है। फिल्म की कहानी एसआई के जीवन की मुश्किलों पर बात करती है। इस पूरे सफर में वह खुद की खोज भी करती है। फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' 28 अगस्त से प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अंबीएका पंडित ने और लेखन अमिता व्यास ने किया है। एएसआई बबीता सिंह उर्फ बेबी का रोल निमिषा सजयन ने निभाया है। वहीं बरुण सोबती और अंशुमान पुष्कर भी अहम भूमिकाओं में हैं।

## अभिनेत्री होने पर शर्मिंदा किया जाता था, अनुपमा ने खोले एक्स के राज

इन दिनों अनुपमा परमेश्वरन अपने व्यक्तिगत जीवन के लेकर चर्चाओं में हैं। अपने पुराने रिलेशनशिप और उससे जुड़े दर्द के बारे में अब वह खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने अपने तकलीफ भरे रिश्ते के बारे में काफी कुछ बताया। जानें क्या कहा एक्ट्रेस ने...

बीते कई दिनों से एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन ने ध्यान वर्मा के यूट्यूब चैनल पर रिश्ते को लेकर कई खुलासा किये हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनके पार्टनर ने रिलेशनशिप के दौरान उनका उत्पीड़न किया। अनुपमा ने बताया एक समय मैं ग्यारह बच्चे पैदा करने का सपना देखती थी। मगर इस रिश्ते के बाद अब मैं बच्चे ही नहीं चाहतीं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे आत्मविश्वास और पेशेवर उपलब्धियों के लेकर कई बार मुझे बहुत बुरा महसूस करवाया। इस रिश्ते ने मेरे निजी जीवन और करियर दोनों में लिए गए मेरे कई फैसलों को प्रभावित किया। मुझे कई बार एक महिला होने और यहां तक कि मेरे एक्टर होने पर भी शर्मिंदा महसूस कराया गया।

अपनी बातचीत में आगे अनुपमा परमेश्वरन ने कहा, ' पीरियड्स का पहला दिन हो, पांचवां दिन हो, दसवां दिन हो, पंद्रहवां दिन हो, बीसवां दिन हो, पच्चीसवां दिन हो, कोई भी दिन हो। अगर आप किसी व्यक्ति से उसकी गलती के बारे में पूछें, तो वो कहेगा- 'अरे, आपको पीएमएस हो रहा है, आपका पीरियड अभी आना बाकी है।' उसके ऐसा कहने पर मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे औरत होने पर बहुत बुरा लगता था। मुझे अपनी सारी उपलब्धियों पर ही बुरा लगने लगा था।'

'परधा' इवेंट में रोने की वजह बताई

अगस्त 2025 में अनुपमा डायरेक्टर के साथ अपनी फिल्म 'परधा' का प्रमोशन कर रही थीं। प्रेस के साथ सवाल-जवाब के दौरान वह अचानक भावुक हो गई और रोने लगीं। उनकी टीम ने उन्हें शांत कराया और पानी दिया। जब पत्रकार उनसे बार-बार पूछने लगे कि वह इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? तो अनुपमा ने बात को टालते हुए कहा था कि महिला-केंद्रित फिल्म को शूट करना और उसका प्रमोशन करना आसान नहीं था। अब हाल ही में उस घटना को याद करते हुए अनुपमा ने कहा, 'हालात कितने भी मुश्किल हों पर मैं मैं ऐसी नहीं हूं कि स्टेज पर ही रोने लगूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वो सबसे बुरी बातें कही गईं, जो कोई महिला सुनना नहीं चाहती। जिस इंसान को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वही मुझे अंदर से तोड़ रहा था।'

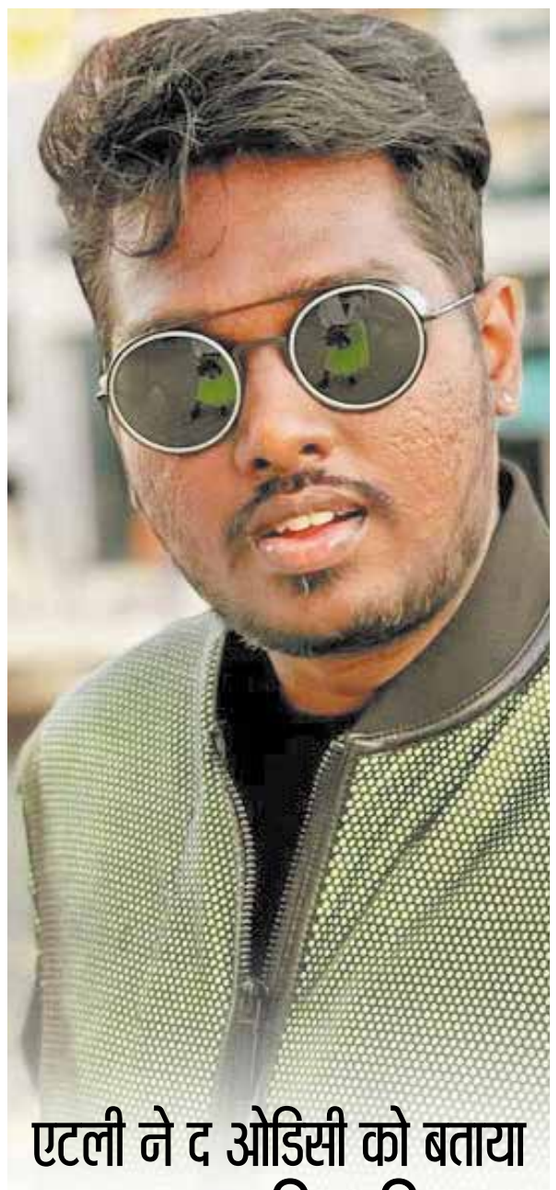

## एटली ने द ओडिसी को बताया ज़बरदस्त एपिक फिल्म, कहानी, विजुअल्स और संगीत की जमकर तारीफ

फिल्ममेकर एटली ने 'द ओडिसी' की जमकर तारीफ करते हुए इसे एक ऐसा सिनेमाई अनुभव बताया है, जो सामान्य फिल्मों से कहीं आगे जाता है। एटली ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए क्रिस्टोफर नोलन की कहानी कहने की शैली, फिल्म के विजुअल्स, सिनेमैटोग्राफी और लुडविग गोरानसन के संगीत की प्रशंसा की है।

अपने अनुभव को साझा करते हुए एटली ने अपनी पोस्ट में लिखा है, 'कुछ फिल्में आप देखते हैं। कुछ फिल्मों की आप तारीफ करते हैं। और फिर, बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो आपको पूरी तरह किसी दूसरी जगह ले जाती हैं। 'द ओडिसी' ने मेरे साथ यही किया।' उन्होंने नोलन की कहानी को 'अद्भुत' बताते हुए यह भी लिखा है कि फिल्म के विजुअल्स अपनी अलग भाषा बोलते हैं और कैमरा भी कहानी सुनाने वाले एक किरदार की तरह महसूस होता है। इसी के साथ लुडविग गोरानसन के संगीत की तारीफ में लिखा है कि यह संगीत सिर्फ फिल्म के साथ चलता नहीं है, बल्कि आपकी धड़कनों में उतर जाता है। एटली ने आगे यह भी लिखा है कि फिल्म में ऐसा एड्रेनालिन और इमर्सिव प्रभाव है, जैसा उन्होंने थिएटर में बहुत कम महसूस किया है। उन्होंने लिखा कि सबसे ज्यादा उनके साथ जो चीज रह गई, वह बेहद व्यक्तिगत थी, जब दर्शक पूरी तरह फिल्म के अनुभव में डूब जाता है, 'तभी एक सच्ची एपिक फिल्म बनती है। उन्होंने लिखा है, 'फिल्म को अपने चारों ओर घेरकर, अपने ऊपर हावी होने दें।

# दीव के वणाकबारा में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ सफल आयोजन

## ■ नागरिकों ने सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लिया लाभ

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दीव 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव के प्रशासक प्रफुल पटेल की दूरदर्शी एवं जनहितैषी सोच एवं मार्गदर्शन में दीव जिला प्रशासन द्वारा 26/08/2026 को प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का दीव के वणाकबारा पंचायत क्षेत्र में सफल आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि यह आयोजन संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के दस साल बेमिसाल समारोह के अंतर्गत 10 वर्षों की परिवर्तनकारी विकास यात्रा के उपलक्ष्य में 26 अगस्त 2026 को वणाकबारा, में किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम करना, नागरिकों तक पहुँचकर उन्हें जागरूकता प्रदान करना एवं सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का सुलभता से लाभ प्रदान करना था। इसके तहत नागरिकों ने बढ-चढकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की और सरकारी सेवाओं का भरपूर लाभ उठाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दीव प्रशासन के तकरीबन 13 विभागों ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ नागरिकों को दिया और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता के साथ 1106 आवेदनों का निपटान किया गया। इस अवसर पर उप समाहर्ता शिवम मिश्रा ने नागरिकों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठाएं और जिला प्रशासन द्वारा पारदर्शिता एवं तत्परता से मुहैया कराई गई त्वरित सेवाओं का लाभ लें। साथ ही नागरिकों को भारत सरकार की योजनाओं तथा विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता भी प्रदान की गई। उप समाहर्ता ने प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉल पर जाकर मुहैया कराई जा रही समस्त सेवाओं का जायजा लिया और नागरिकों से बातचीत करते हुए उनकी व्यवहारिक समस्याओं का संज्ञान लिया और और उनके त्वरित समाधान हेतु मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सेवा प्रदाताओं को नागरिकों को सहज एवं सटीक रूप से सेवायें प्रदान करने हेतु जरूरी निर्देश दिए एवं नागरिकों को संदेश दिया कि आप सरकारी सेवाओं और नियमों के बारे में जागरूक रहें। कार्यक्रम के तहत त्वरित सेवायें प्रदान करते हुए कुछ ग्रामीणों को मौके पर ही आय प्रमाणपत्र, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, ओबीसी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड और लर्निंग लाइसेंस आदि वितरित किए गए और नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच आदि सेवाओं का भी लाभ उठाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दीव जिला के सरकारी कार्यालय जैसे मामलतदार कार्यालय, खंड विकास कार्यालय, शहरी सर्वेक्षण कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, सिविल पंजीकरण कार्यालय, नागरिक आपूर्ति कार्यालय, निर्वाचन प्रकोष्ठ, टोरेंट पावर लिमिटेड, परिवहन विभाग, दीव के लीड बैंक भारतीय स्टेट बैंक तथा और मत्स्य विभाग आदि द्वारा अपनी -अपनी सेवाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर दीव की जनता की समस्याओं को सुना गया और उन्हें प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया। अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध होने पर उनकी समस्याओं का यथा संभव तुरंत समाधान किया गया एवं विभागों से जुड़ी अपेक्षित सेवायें मौके पर ही मुहैया कराई गई। इस प्रकार प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नागरिकों को आज कुल 1106 सेवायें प्रदान की गईं। कार्यक्रम के तहत आयोजित रोजगार मेले में रोजगार के इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 19 नियुक्ति आदेश प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए नागरिकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का उनके द्वार पर समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत आयोजित रोजगार मेले में रोजगार के इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 19 नियुक्ति आदेश प्रदान किए गए। ज्ञात हो कि 27 अगस्त 2026 को शहरी क्षेत्र दीव में झँपा गेट, साईं मंदिर के पास प्रशासन आपके द्वार का आयोजन किया जाएगा।

# संघ प्रदेश में विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में खानवेल में निकाली गई बाइक रैली

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव में प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन दादरा नगर हवेली द्वारा आज खानवेल में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन खानवेल चार रास्ता से वाघचौडा होते हुए दुधनी रोड तक किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम केक काटकर प्रशासक प्रफुल पटेल के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए गौरवपूर्ण विकास कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित की गईं। तत्पश्चात हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सिलवासा नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पार्षदगण तथा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। रैली में जिले के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों से आए बाइक राइडर्स एवं ऑफ-रोड राइडर्स ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। प्रतिभागियों ने पूरे उमंग एवं उत्साह के साथ रैली में शामिल होकर संघ प्रदेश में पिछले 10 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों के प्रति अपनी सहभागिता और समर्थन व्यक्त किया। विकास यात्रा के गौरवपूर्ण 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रैली के दौरान विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाती दो आकर्षक विकास रथ झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। यह बाइक रैली एकता, विकास और जनभागीदारी का संदेश देने के साथ-साथ संघ प्रदेश की विकास यात्रा के 10 गौरवपूर्ण वर्षों के उत्सव का प्रतीक बनी। विभिन्न पंचायत क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं एवं नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने कार्यक्रम को और अधिक सफल एवं आकर्षक बनाया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने संघ प्रदेश में हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए प्रशासक प्रफुल पटेल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। जिला प्रशासन ने रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले सभी राइडर्स, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संघ प्रदेश की विकास यात्रा में जनभागीदारी एवं सामूहिक प्रयास सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

# दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल ने भीमपोर पंचायत घर पर आयोजित प्रशासन आपके द्वार शिविर का किया दौरा

■ प्रशासक प्रफुल पटेल के 10 वर्षों के कार्यकाल को बताया बेमिसाल ■ जिला पंचायत सदस्यों और सरपंचों के साथ भीमपोर आश्रमशाला परिसर में किया सामूहिक वृक्षारोपण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 26 जनवरी। दमण जिला पंचायत के अध्यक्ष धरम पटेल ने संघ प्रशासन के सुशासन के 10 साल बेमिसाल के तहत भीमपोर ग्राम पंचायत घर पर 26 अगस्त को आयोजित प्रशासन आपके द्वार शिविर का दौरा किया। यह प्रशासन आपके द्वार मरवड़, कड़ैया, भीमपोर, दुनेठा, भेंसलोर और वरकुंड ग्राम पंचायतों का संयुक्त शिविर रहा। इन छहों ग्राम पंचायतों के सरपंच ग्रामीणों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ दिलाने को शिविर में मौजूद रहे। शिविर में पहुँचने पर उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल का अभिवादन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल ने भी सभी सरपंचों का कुशलक्षेम जाना। प्रशासन आपके द्वार में स्वास्थ्य जाँच शिविर, रक्तदान शिविर और ग्रामीणों के लिए विभागीय सेवाओं संबंधी शिविर भी हुए। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जाँच और सरकारी सेवाओं का लाभ लिया। राशन कार्ड, आधार कार्ड, 7/12 नकल, सामाजिक सुरक्षा पेंशनों आदि सेवाओं के लिए ग्रामीणों ने आवेदन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल ने प्रशासन आपके द्वार शिविर का दौरा कर स्टॉल पर मौजूद कर्मियों को ग्रामीणों को तत्परता पूर्वक सेवा प्रदान करने को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी ग्रामीणों को सेवाओं का लाभ दिलाते देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल का कहना था कि प्रशासक प्रफुल पटेल के दस वर्षों के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत सुविधाओं सहित सभी क्षेत्रों में अभिनव एवं अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ है। उन्होंने 27 अगस्त को मगरवाड़ा ग्राम पंचायत-घर पर पटलारा, मगरवाड़ा, दमणवाड़ा और परियारी ग्राम पंचायतों के लिए लगने वाले प्रशासन आपके द्वार शिविर का उपरोक्त गाँवों के लोगों को लाभ लेने का आह्वान किया। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। ज्ञात हो कि दमण जिला पंचायत अध्यक्ष धरम पटेल, जिला पंचायत सदस्यों और सरपंचों ने भीमपोर आश्रमशाला के परिसर में सामूहिक वृक्षारोपण भी किया।

# दमण जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दस साल बेमिसाल के तहत सफाई अभियान के साथ हुआ वृक्षारोपण

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 26 जनवरी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव की 10 साल की बदलाव लाने वाली विकास यात्रा के जश्न के तौर पर दस साल बेमिसाल थीम के तहत दमण जिले की सभी 16 ग्राम पंचायतों में 24 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक एक खास सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस खास सफाई अभियान को पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि लीड कर रहे हैं, जिनमें सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और वॉर्ड सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने अपने-अपने पंचायत इलाकों में सफाई की एक्टिविटी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान में जिले की सभी मुख्य सड़कों, अंदरूनी और गांव की सड़कों, पब्लिक जगहों, धार्मिक स्थलों, बीच, हाट और बाजार की जगहों पर सफाई की एक्टिविटी शामिल हैं, जो पूरे जिले में अलग-अलग जगहों को कवर करती हैं। कैंपेन के एक जरूरी हिस्से के तौर पर, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के मुताबिक, कचरे को चार तरह से अलग करने और सोर्स पर ही अलग करने को बढ़ावा देने के लिए घर-घर जाकर जागरूकता फैलाने की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। इस पहल का मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना और घर एवं सामुदायिक स्तर पर जिम्मेदार वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों को बढ़ावा देना है। स्पेशल सफाई ड्राइव का एक मुख्य फोकस ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सभी ऐसे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स की पहचान करना है। इन पहचानी गई जगहों को सिस्टमैटिक तरीके से साफ किया जा रहा है और बेहतर बनाया जा रहा है, ताकि लगातार सफाई बनी रहे और कचरा दोबारा जमा न हो। कैंपेन के हिस्से के तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि हरियाली और सेहतमंद माहौल को बढ़ावा दिया जा सके और सार्वजनिक जगहों की खूबसूरती बढ़ाई जा सके। स्पेशल सफाई ड्राइव संघ प्रशासन के सिविक हाइजीन बनाए रखने, कम्युनिटी की भागीदारी को मज़बूत करने और सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के तरीकों को बढ़ावा देने के लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। चुने हुए प्रतिनिधियों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी दमण को ज्यादा साफ, स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ बनाने में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को और मजबूत करती है। साथ ही दास साल बेमिसाल के तहत बदलाव लाने वाले विकास के एक दशक का जश्न भी मनाती है।

स्वामी: मारुतिनंदन पब्लिक, संपादक, प्रकाशक व मुद्रक विजय जगदीशचंद्र भट्ट द्वारा गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल, नानी दमण - 396210 से प्रकाशित तथा असली आजादी प्रेस गाला नं. 7, तिरुपति इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सोमनाथ मंदिर रोड, दाभेल नानी दमण - 396210 से मुद्रित।
(समाचारों के चयन के लिए संपूर्ण जिम्मेदारी पीआरबी एक्ट के अंतर्गत संपादक की होगी। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दमण न्यायालय के अधीन होगा।)